ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

Study of a New Species of Trematode Parasite Found In the Fresh Water Fish *Mystus Vittatus* (Bl.) From River Ganga at Kanpur

Anupam Yadav
Department of Zoology,
S.G.M. Degree College,
Rasulabad,
Kanpur Dehat.

Abstract

About one hundred twenty specimens of *mystus vittatus* (Bl.) were collected from river Ganga in district Kanpur out of these only two hosts were found infected with four trematode parasites. Parasits resides in the stomach of host. The parasite has been referred to the genus *Allocreadium Loss*, 1902.

The new form *Allocreadium gangaensis* has a close resemblance with *A. handiai* Pande, 1937; *A. thapari* Gupta, 1950, the new species shows differences in the size of oral sucker, ventral sucker and position of ovary.

The differences are also found with *A. manteri* Gupta and Puri, 1980 in having the overlapping testes instead of non overlapping and non operculated eggs instead of operculated eggs.

Key Words: *Mystus Vittatus*, Ganga River, *Allocreadium Gangaensis*

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

Higher Education: Problems, Challenges and Solutions

Manoj Kumar Yadav
Assistant Professor
Deptt of Mechanical Enggineering
Pranveer Singh Institute of Technology
Kanpur

Abstract

Education plays an important role in the development of a country. The improvement in quality of higher education is a big challenge for educationalists. To survive in global market country needs innovative professionals with knowledge of multidisciplinary areas. But there are many obstacles in achieving this goal. The main obstacle is conventional education system which emphasizes on gaining much marks in examinations. For gaining good marks in examination students start learn the topics without understanding the theory behind it. Here a student kills his creativity. Diverting the education system from conventional to new one is a big challenge. The gap between current education system and need of global market can be filled to an extent by doing some amendments in education system. The new education system needs to focus on creating such professionals which can identify the problems and give proper solutions to those problems. The system of education must incorporate industrial visits and trainings instead of increasing load of subjects on students.

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा : एक चुनौती

नलिनी सिंह
शोध छात्रा
जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग वि.वि.
चित्रकूट

सारांश

उच्च शिक्षा किसी भी देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। वह विविध क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करती है। यह एक सांस्कृतिक वातावरण बनाती है जिनमें जाति, क्षेत्र भाषा, धर्म और राजनीतिक विचार धराओं का व्यापक रूप में समन्वय होता है। वह युवाओं के समाजशास्त्र व मनोविज्ञान को बल देती है और उनके कैरियर को व्यापक अवसर प्रदान करती है। हमारे देश में युवा असंतोष अनेक समस्याओं का कारण है जिसका सम्बन्ध उच्च शिक्षा से ही है।

प्रस्तावना

आज जब हम उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में विचार करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अक्षम है, न सर्व सुलभ है और न ही उसमें कहीं गुणवत्ता नजर आती है। जिस देश में कभी उच्च गुणवत्ता वाले कई विश्वविद्यालय एवं संस्थान हुआ करते थे जिनकी ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त थी। पूरी दुनिया से छात्र इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए खिंचे चले आते थे। वे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के साथ अनेक कौशलों में प्रवीणता अर्जित करते थे। साथ ही साथ उच्च संस्कार में दर्शनशास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षा संसार के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों द्वारा दी जाती थी।

किसी देश की सम्पन्नता तथा विकास उस देश के विश्वविद्यालयों सें जुड़ा होता है। विश्वविद्यालयों के दूषित हो जाने पर पूरा राष्ट्र दूषित हो जाता है। वास्तव में उच्च शिक्षा ही राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। जब पूरी दुनिया ने विद्यालय की कल्पना नहीं की थी उस समय हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिक्षा विश्वविद्यालय, विक्रम शिला विश्वविद्यालय भारत की धरती पर थे। परन्तु सही अर्थो में आधुनिक उच्च शिक्षा का श्री गणेश 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' ने 1781 में 'कलकत्ता मदरसा' एवं 1791 में कम्पनी ने ही बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना की। परन्तु इसके पाठ्यक्रम का संचालन इग्लैंड द्वारा ही किया जाता था। उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास दूरदर्शी तथा बुद्धिमान बनाना था जो राजनीति प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें। परन्तु स्वतंत्रता पश्चात उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं शोचनीय हो गयी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राधाकृष्णन् आयोग, कोठारी आयोग नयी शिक्षा नीति जैसे अनेक आयोगो का गठन किया, जो कि एक सराहनीय कदम था, परन्तु फिर भी उच्च शिक्षा का उचित विकास नहीं हो सका। जिसका कारण उच्च शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्यायें एवं चुनौतियां थी। उच्च शिक्षा के मार्ग को बाधित कर रही थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक

चुनौतियां हमारे समक्ष दिखायी देती हैं जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम की शुरूआत तो हो गयी लेकिन शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पाठ्यक्रम का समय से पूर्ण न होना, योग्य शिक्षकों उचित वेतन एवं पदोन्नति का अवसर न मिला, अनुसंधान कार्यो की कमी, बेरोजगारी छात्रों का निराशावादी माहौल उच्च शिक्षा केन्द्रों को विश्वस्तरीय स्थान दिलाने में असफल हो रहें हैं। उच्च शिक्षा केवल अर्द्ध शिक्षित बेरोजगारों की फौज ही खड़ा कर रहा है। उच्च शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आरक्षण, राजनीति तथा व्यवस्था तंत्र भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दलों का प्रवेश छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा अब दान की वस्तु नहीं अपितु सियासत की वस्तु बन गयी है। इन्ही अव्यवस्थाओं के कारण छात्रों में अनुशासन हीनता, आक्रोश आदि चुनौती बनकर हमारे समक्ष खडी है फलस्वरूप प्रतिभाशाली लोग विदेशों की ओर पलायन कर रहें हैं। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसका एकमात्र उपाय है राजनीति को शिक्षा से बिल्कुल अलग रखा जाए नही तो छात्रों को न रोजगार मिलेगा और न ही वे किसी छोटे–मोटे कार्य करने के योग्य रह जायेंगे। उर्दू कविता के एलेक्जेंडर पोप कहे जाने वाले अकबर इलाहाबादी ने इस स्थिति को भाँपते हुए कहा था–

न पढ़ते तो खाते सौ तरह कमा कर, मारे गये हाए तालीम पाकर।
न खेतों में रहट चलाने के काबिल, न बाजार में माल ढ़ोने के काबिल।

हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र नेट, पी–एच.डी. जैसी बड़ी–बड़ी उपाधि तो प्राप्त कर लेते है, किन्तु पचास की आयु तक पहुँचने पर भी उनको उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती है। फलतः वह कुण्ढा का शिकार होकर अपने पथ से विमुख हो जाते हैं। यदि हम दूरदर्शी नीति को लागू करते है और राष्ट्रनिर्माता कहें जाने वाले अध्यापक, जागरूक अभिभावक व जिज्ञासु विद्यार्थी अपने समन्वय का प्रण करते हैं, तो इस विकासशील देश को डा. कलाम के सपनों का ओजस्वी नवशक्त और विकसित मानव संसाधन युक्त भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा की समस्यायें

नीतू तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
जे0आर0एच0यू0,
चित्रकूट

जयकिशोर तिवारी
शोध छात्र
जे0आर0एच0यू0
चित्रकूट

सारांश

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालयो विशिष्ट शिक्षा संस्थानों आदि में प्रदान की जाती है। प्राचीन मध्यकाल में कुछ उच्च शिक्षा केन्द्र प्रसिद्ध थें परन्तु आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्वरू‹ अंग्रेजी शासन की देन है। किसी देश की सम्पन्नता का भाग उस देश के विश्वविद्यालयो से जुडा होता है।

विश्वविद्यालयों में दूषित शिक्षा होने से सम्पूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाता है। वास्तव में उच्च शिक्षा, शिक्षा का वह स्तर है जों देश के प्रत्येक क्षेत्रो में नेतृत्व प्रदान करता है। जिस स्तर का नेतृत्व देश की उच्च शिक्षा विकसित करेगी, उसी स्तर तक देश का विकास सम्भव हो सकेगा।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी जिसके परिणाम स्वरूप उसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं थें न ही उसका पाठ्यक्रम निश्चित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त उसका संख्यात्मक विकास अत्यन्त धीमी गति से हुआ किन्तु नियोजन की दशा सही न होने के कारण उच्च शिक्षा का स्तर गिर गया एवं उच्च शिक्षा का उद्देश्य विहीन हो गयी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की उपयोगिता समाप्त जैसे हो गयी। परिसर के हाल एवं छात्राओं में अशान्ति जैसे भावनाये फैल गयी। अतः विद्वान व्यक्तियों कि समय बेरोजगारी की समस्या पूर्ण रूप से व्याप्त होने लगी। वर्तमान में उच्च शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हों गया है। आज के आधुनिक समय में उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य बन गया है। डिग्री प्राप्त करना उच्च शिक्षा में दाखला लेने वाले विद्यार्थीयों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नही हो पाता आज शिक्षित व्यक्ति ही विध्वंसक प्रवृत्तियों के शिकार हो रहे हैं।

प्रमुख समस्याएँ

हमारे देश में प्रशासन वित्त एवं नियंत्रण के अनुसार तीन प्रकार के विश्वविद्यालय है। केन्द्रीय राज्य एवं समकक्ष विश्वविद्यालय इनका देखरेख केन्द्र सरकार स्वयं राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक संस्थाओं के हाथ होता है। राजनैतिक दबाव से जगह जगह पर महाविद्यालय स्थापित कर दिये गये है अब विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों के प्रशासन उनकी वित्तीय व्यवस्था करने में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव हो रहा है। महाविद्यालयो में प्राचार्यो को काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को कई स्तर पर स्ववित्तपोषित करने की दिशा में कदम उठ़ाये जा चुके है। इसकें परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के छात्रों का अधिक शोषण हो रहा है। आज के आधुनिक समय में उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने की समस्या बडी कठिन हों गयी है प्रायः महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। परन्तु यह भीड यदि ज्ञान पिपासुओं की होती तों देश का बहुत सौभाग्य होता परन्तु दुख इस बात का है

कि उच्च शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य नौकरी पाने के लिये या डिग्री प्राप्त करना रह गया है। उच्च शिक्षा सस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नही है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जीवन से अलग है। आधुनिक विकासवादी युग में उसका योगदान बहुत कम हैं। पाठ्क्रम छात्रों को सूचनायें देता है। आज का पाठ्यक्र नीरस और संकीर्ण है, प्रचलित पाठ्यक्रम छात्रों की रूचि और मनोवृति के अनुरूप नहीं है। पाठ्यक्रमों में कार्यनुभव को स्थान नहीं दिया।

1. माध्यम की समस्या
2. शैक्षिक स्तर की समस्या
3. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली की समस्या
4. अनुशासन की समस्या
5. निर्देशन सेवाओं की समस्या व अभाव
6. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या

समाधान–

उच्च स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को अपनाना चाहिए अतः जो लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहें उन्हें पूरा अवसर मिलना चाहिए वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार करना चाहिए। परीक्षाओं को अधिकाधिक वैज्ञानिक विश्वसनीय एवं वैध बनाने की आवश्कता है। अनुशासन समस्या समाधान के लिए छात्र शिक्षक अभिभावक आदि सभी समलित है एवं सबकी जुम्मेदारी है। निर्देशन सेवाओं के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन एवं परामर्श की सेवाएँ दी जायें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाये जाने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लियें सबसे अधिक ध्यान दिया जाये कि केवल योग्य महात्व विद्यार्थीयों को प्रवेश दिया जाये।

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं में से कुछ को हल किया जा चुका है, अस्तु कुछ समस्याओं का निवारण करना शेष रह गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमें सर्वप्रथम उन समस्याओं को हल करना चाहिये जो हमारे उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उसी की समस्याओं को हल करने के लिए दो साधन चाहिये–

1. वित्तीय संसाधन 2. कार्यरत् ईमानदार व्यक्ति और कर्तव्यनिष्ठा। यदि सरकार उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था में पर्याप्त धनराशि लगा दी और उच्चशिक्षा से जुड़े हुए लोग ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करे तो पूरा जग जीता जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *गुप्ता एस0पी0–भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें।*
2. *सारस्वत मालती–भारतीय शिक्षा का विकास, समायिक समस्यायें।*
3. *मदान, पूनम– भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें।*
4. *लाल, बिहारी रमन– भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्यायें।*

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षको की दशाओ पर अध्ययन

सुनील कुमार पाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
एल. आर. पी. जी. कालेज
इटावा

सारांश

भारतीय समाज में गुरूओ का स्थान ईश्वर से बड़ा है। परन्तु वर्तमान समय आर्थिक युग का है। इसमें धन का स्थान सबसे ऊपर है। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के विकास की प्रमुख आधारशिला है। उत्तर प्रदेश में उच्चशिक्षा की दशा बहुत अच्छी नही है। प्रदेश में 90 प्रतिशत शिक्षा के विकास में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो का योगदान है। उत्तर प्रदेश में 331 महाविद्यालय सरकार की सहायता से वित्तपोषित है। और 135 राजकीय महाविद्यालय संचालित है। उच्चशिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम सन् 1948 में डॉ0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गहन अध्ययन व विचार विर्मश के पश्चात सस्थाओ को स्वायत्तता प्रदान करने की सस्तुति प्रदान की गई है। वर्ष 1995–96 से स्ववित्तपोषित योजना को प्रारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तरगत संचालित पाठयक्रम में शासानादेश संख्या – 2443/सत्तर –2–2000–2(85)/97 9 मई 2000 एवं शासंनादेश संख्या – 4503/सत्तर –2–2000–2(85) /97 दिनांक 31 अगस्त , 2000 के प्राविधान के अन्तर्गत शिक्षको की नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्रावधानो को लागू सही ढग से नही किया जा राह है। विगत समय पूर्व समाचार पत्रो के माध्यम से जानकारी मिली कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में एक ही शिक्षक कई महाविद्यालयो मे अध्यायपन का कार्य करते हुए पाये गये है । तथा ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में 2016–17 में 80 हजार प्रोफेसर चार – चार जगह नौकरी करते पकडे गये है। और सभी जगह से वेतन भी लेते हुए पकडे गये है। समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्व निजी महाविद्यालय लखनऊ शहर में ऐसे है। जिनमें अनुमोदित शिक्षको के स्थान पर इन्टरमीडिएट या उससे कुछ अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शिक्षण कार्य करता हुआ प्राप्त हुआ है।

शोध परिकल्पना

1. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयो में कार्यरत अध्यापको से सम्बन्धित समस्याओ का अवलोकन
2. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयो में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षको एवं कर्मचारियो की आर्थिक दशाओ का आंकलन करना
3. स्ववित्त पोषित शिक्षण सस्थाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो के शिक्षा के स्तर का अवलोकन करना

शोध पत्र के उद्देश्य एवं प्रविधि

1. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयो में कार्यरत अध्यापको के आर्थिक , मानसिक शोषण की स्थिति का अध्ययन करना

2. स्ववित्त पोषिण शिक्षण सस्थाओ में शासनादेशो को सही ढग से न लागू करने की दशाओ का अध्ययन करना
3. स्वविप्त पोषित संस्थाओ में शिक्षण कार्य का अवलोकन आदि बिन्दुओ का अध्ययन

शोध विधि

यह शोधपत्र स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापको पर होने वाले शोषण पर अध्ययन किया है। विभिन्न स्ववित्तपोषित शिक्षण सस्थाओ के 50 अध्यापको का चयन किया है। जिसमें साक्षात्तकार के माध्यम से उन्होने स्व वित्तपोषित सस्थाओ में उनके ऊपर हो रहे शोषण से अवगत कराया है। तथा इसमें संमको का कम से कम प्रयोग किया है ।

स्ववित्त पोषित शिक्षण सस्थाओ में अध्यापको की निम्नलिखित समस्याए है।

स्ववित्तपोषित शिक्षण सस्थाओ में आर्थिक शोषण

स्ववित्तपोषित शिक्षण सस्थाओ में अध्यापको का आर्थिक शोषण एक आम समस्या हो गई है। उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन तो दूर एक अकुशल श्रमिक से भी कम दिया जाता है। ाअैर फर्जी तरीके से उनके बैक खाते खोले जाते है। और उनमें पैसे डाले और निकाले जाते है। कुछ अध्यापको के चेक बुक पर साइन करालिए जाते है। और कुछ के ए.टी.एम. आपने पास रख लिए जाते है । और इस प्रकार का धन्धा वर्षा से चला आ रहा है। और अध्यापक इसका विरोध करता है। तो उसको फर्जी आरोप लगाकर सस्थान से निकाल दिया जाता है।

स्ववित्तपोषित शिक्षण सस्थान में मानसिक शोषण

इन सस्थाओ में कार्यरत अध्यापको में कार्य के घन्टे भी निर्धारित नही है। उनको 8 से 12 घन्टो तक बिना आराम किये कार्य पर लगा दिया जाता है । शिक्षण कार्य में अतिरिक्त भी उनसे अनेक कार्य करवाए जाते है। जो नियम के विरूद्व होते है। जिसके कारण उनकी शिक्षण रूचि पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
स्ववित्तपोषित शिक्षण सस्थानो मे अध्यापको के शोषण रोकने के उपाय –

1. स्ववित्तपोषित सस्थानो के अध्यापको का वेतन यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित सरकार द्वारा किसी अधिकृत शासनीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए ।
2. इन सस्थाओ की निगरानी उच्च अधिकारियो जिसमें जिला अधिकारी रेंक के अधिकारी से प्रत्येक माह कराई जानी चाहिए ।
3. विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए ।
4. छात्र संख्या के अनुसार अध्यापको की नियुक्त होनी चाहिए ।
5. स्वविस पोषित शिक्षण सस्थानो मे अध्यापको की कार्य करने का समय निर्धारित होना चाहिए और उसे कगई से पालन करना चाहिए

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

आधुनिक शिक्षण प्रणाली में श्रीमद्भगवद्गीता की उपादेयता : उच्चशिक्षा के सन्दर्भ में

अंजू वर्मा
शोध छात्रा
संस्कृत विभाग
कानपुर विद्या मन्दिर (पी0जी0) महिला महाविद्यालय
स्वरूप नगर, कानपुर

श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्ण विश्व के विद्वानों का आकर्षण केन्द्र है। सम्पूर्ण वाङ्.मय का मुकुट है, मानवता की अमूल्य निधि है तृथा समग्र संसार के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा के लिए अक्षय पाथेय है। भक्तियोग, ज्ञानयोग एवं कर्मयोग का समन्वय श्रीमद्भगवद्गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। यथोहि उक्तं च –

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।

(श्रीमद्भगवद्गीता 2.43)

श्रीमद्भगवद्गीता में जीवन के प्रत्येक पक्ष के लिए ऐसी–ऐसी महत्वपूर्ण उपदेश दिये गये हैं जिसके अध्ययन से कोई भी मनुष्य निराशावादी से आशावादी बन सकता है। गीता सर्वप्रथम बुद्धि के निर्मलीकरण एवं विकास पर बल देती है, इसके अभाव में कोई भी शिक्षा सार्थक नहीं हो सकती। वर्तमान उच्चशैक्षिक परिवेश में गीता का शैक्षिक मूल्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रकाशित करती है। यह प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के प्रत्येक आयाम पर ध्यान केन्द्रित करती है और उसको विकसित करने के लिए शिक्षा एवं प्रेरणा देती है। श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन मात्र वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि अध्यापक माता–पिता एवं संसार के समस्त प्राणियों के लिए उपयोगी है। प्रत्येक मनुष्य में मानवता जाग्रत हो, हमारा जीवन एकांगी न होकर समाज के लिए हितकर बने। यह ग्रन्थ विश्व एकता के निर्माण पर बल की शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान परिवेश में 'गीता' की शिक्षा की उपादेयता सर्वाधिक है। वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात की जा रही है उसके समाधान मे गीता दर्शन एवं शिक्षा एक उपयोगी साधन है।

श्रीमद्भगवद्गीता विश्व साहित्य की अति आदरणीय एवं अमूल्य निधि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश मानव जीवन की अनगिनत जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करता है। 'गीता' में वेदान्त दर्शन का सारतत्व निहित है। वैदिक साहित्य का

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद् स्वीकारते हुए विद्वानों ने इसे 'गीतोपनिषद' संज्ञा से समलंकृत किया है। स्वामी विवेकानन्द ने गीता के रचनाकार को मानव जाति का श्रेष्ठतम् व्यक्ति माना है।[1]

डा0 राधाकृष्णन गीता को भारतीय दर्शन एवं चिन्तन पर प्रभावी मानते है।[2] 'बालगंगाधर तिलक' 'श्रीमद्भगवद्गीता' को अभूतपूर्व ग्रन्थ स्वीकार करते हैं।[3] यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वर्तमान युवा पीढ़ी के सामाजिक जीवन की सभी समस्याएँ 'गीता' के अध्ययन से सुलझ सकती है। आधुनिक युग के बहुत से दार्शनिक, वैज्ञानिक गीता से प्रेरणा पाकर ही अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। गीता देश काल से परे हैं।

वर्तमान उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे शिक्षार्थियों के ज्ञानवर्द्धन के लिए श्रीमद्भगवद्गीता की महती उदादेयता है। विद्यार्थियों के लिए 'गीता' में नम्रता, जिज्ञासा और सेवा इन तीन बातों का होना परमावश्यक बताया गया है – तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया[4] अर्थात् तुझे यदि विद्या प्राप्त करनी है तो तेरे पास प्रणिपात् अर्थात जिज्ञासा और सेवा इन तीन बातों का होना अत्यावश्यक है। नम्रता के अभाव में स्थाई ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं होती। गुरु से प्राप्त ज्ञान से गुरु सेवा करने पर वह अत्यधिक उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। इस प्रकार 'गीता' में कहा गया है कि श्रृद्वावान व संयमी को ही ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षार्थी के साथ–साथ 'गीता' में शिक्षकों की योग्यता के विषय में शिक्षकों की योग्यता के विषय में भी कहा गया है –

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः[5] अर्थात् ज्ञान का उपदेश देने वाला व्यक्ति ज्ञानी व तत्त्वदर्शी होना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षक या गुरु विचारों से विद्वान व आचरण से सज्जन होना चाहिए।

वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए श्रीमद्भवद्गीता का यह संदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को तत्त्वदर्शी होने के साथ–साथ ऐसा होना चाहिए कि उनका जीवन अनुकरणीय हो। उन्हें ज्ञान–विज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण रागद्वेष से परे होना चाहिए, व्यक्तित्व दैवीय होना चाहिए। यदि ऐसे शिक्षक हमारे देश में होंगे तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली और अधिक सृदृढ़, व्यापक एवं मौलिक हो सकती है। 'गीता' में शिक्षा जगत् को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और यह कहा गया है कि शिक्षक का जीवन समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय हो। उसकी जीवन प्रणाली आचार–विचार से पवित्र होनी चाहिए एवं उसमें पठन–पाठन के प्रति अतिशय प्रेम होना चाहिए। एक शिक्षक का व्यक्तित्व एकांगी न होकर सर्वांगी होना चाहिए जो वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन सके। यदि वर्तमान समय में गीता के विचारों का पालन प्रमाणिकता से करेंगे तो अवश्य ही शिक्षा जगत को एक नयी आशा एवं नयी किरण प्रदान कर सकेंगे।

निष्कर्षतः हम सकते हैं वर्तमान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमद्भवद्गीता पूर्णरूपेण प्रासंगिक हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तप को अंगीकृत करने का प्रयास

---

1 Swami Vivekanand : Thought on the geeta, Calcutta, 1974 P .4

2 Dr. S. Radha Krishan, Indian Philosophy, Vol -1, London, 1929, P - 519

3 B.G. Tilak, Gita Rahasya Eng. : Tra. by B.S. Sukthankard -1, Poona 1935, P. Vol -1, London, 1929, P – 519, P Author's Preface.

4 श्रीमद्भगवद्गीता 4 / 34

5 श्रीमद्भगवद्गीता 4 / 34

करें जिसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसंयम एवं लक्ष्य के प्रति एकाग्रता का विकास होगा। जिसके परिणाम स्वरूप वे व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास एवं राष्ट्रिय विकास कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का शैक्षिक मूल्य आज भी उतना ही पूर्ण व्यवहारिक है, जितना आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व था। यदि आज शैक्षिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से गीता के मूल्यों का पाठन हो तो निश्चित रूप से यह भारत कुछ वर्षों में विश्व पटल पर एक ऐसे दमकते सितारे के रूप में दिखाई देगा जिसका सपना हमारे प्राचीन गुरुओं एंव मार्गदर्शकों ने देखा है। हमें उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए यह सूक्ष्म कदम अवश्य उठाना चाहिए।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्चशिक्षा का बदलता स्वरूप : एक विश्लेषण

दिव्या मिश्रा
शोध छात्रा
संस्कृत विभाग
कानपुर विद्या मन्दिर महिला पी0जी0 महाविद्यालय
कानपुर

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन से ही विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। आदिकाल से मानव–जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवास, शिक्षा, आचार–विचार, भोजन आदि प्रत्येक क्षेत्रों में परिवर्तन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो समाज को वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल बनाने में प्रयास करता है, उन्हीं में शिक्षा एक अभिन्न अंग के रूप में मनुष्य से सम्बद्ध है। 'ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है।[6] वैदिक काल में शिक्षा देने की प्रमुख संस्था एक मात्र गुरुकुल थी, जहाँ शिष्य प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा तक ज्ञान को ग्रहण किया करते थे। उस काल की शिक्षा का एकमात्र उद्घोष था –

''तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये।
आयासायापरं कर्म विद्यऽन्या शिल्पनैपुणम्।''[7]

अर्थात् कर्म ही जो बन्धन का कारण न हो, विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्यायें कला–कौशल मात्र ही हैं। उपरोक्त कथन आधुनिक समय में पूर्णतया चरित्रार्थ हो रहा है। वर्तमान समय की शिक्षा में जितना कर्म की आवश्यकता है उससे अधिक छात्र–छात्राओं में कौशल को विकसित करना भी नितान्त आवश्यक है। ऋग्वेद में भी वर्णित है कि 'सहस्त्रधारा पयसा मही गौः' शिक्षा सहस्त्रधारा से दूध देने वाली कामधेनु है। वर्तमान समय में यही शिक्षा अनेक आयामों के रूप में विकसित होती आ रही है। दीर्घकालावधि के अनन्तर उच्चशिक्षा के प्रारूप, स्वरूप, विधि आदि अनेक उपागमों में तकनीकीकरण प्रविधियों का विशेष रूप से प्रयोग होने लगा है। जो उच्च शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप के लिए एक उपलब्धि के साथ चुनौती भी प्रस्तुत करता है। तक्शी सामाकाटो, ''शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों, जैसे– शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य–वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण विद्यार्थियों एवं निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अन्तः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है।''[8] इससे समावेशित रूप से उच्चशिक्षा में विकास हो सके।

6 शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, अनुपमा सिंघल, एस0पी0 कुलश्रेष्ठ, पृ0 5
7 विष्णुपुराण 1/19/41
8 शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, अनुपमा सिंघल, एस0पी0 कुलश्रेष्ठ, पृ0 8

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने इस तकनीकीकरण पर विशेष बल दिया है जिसमें शैक्षिक संस्थाओं हेतु ''डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल'' तैयार किया है। उसमें सभी शैक्षिक संस्थाओं को 17 सूत्रीय एजेण्डा की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

देश के सभी विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं को ''राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बनना अनिवार्य है जिससे सभी जिज्ञासुओं के लिए सुगमता से सभी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें जिससे छात्रों को उच्चशिक्षा के विषय में नवीन जानकारी भी प्राप्त हो सके।

वर्तमान समय में कम्प्यूटरीकरण का युग है जिस प्रकार प्राथमिक, शिक्षा को 'स्मार्ट क्लास' से जोड़ा गया है उसी प्रकार प्रत्येक संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भी जोड़ा जाए। जिसमें छात्राओं में विषय के प्रति रुचि जाग्रत हो सके और उनमें अध्ययन के प्रति प्रवृत्ति में वृद्धि भी होगी। ''स्मार्ट क्लास' में अध्यापन करते समय यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि विद्यार्थियों के पास उस विषय से सम्बद्ध पुस्तक भी होना अनिवार्य हो। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में समय–समय पर पाठ्यक्रम में नवीनता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। जिससे वह अपने विषय में हो रहे आधुनिक ज्ञान से भी भलीभांति परिचित रहें।

भारत देश को अगर वर्ष 2020 तक सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए योग्य छात्र–छात्राओं एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हम सभी को अधिक संख्या में उच्चशिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी स्वयं को कैसे ज्ञानवान बनायें ? जिससे उच्चशिक्षा में सकारात्मक विकास किया जा सके।

इस प्रकार उच्चशिक्षा में तकनीकी एवं पाठ्य विषय के साथ सामंजस्य होना अति आवश्यक है क्योंकि अति किसी की भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। इसके साथ उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को विषय में निपुणता प्रदान कराने के साथ ही उसके अन्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक, धार्मिक, बौद्धिक आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का समय–समय पर आयोजन कराना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन कोनवीन विचार धारा प्रदान करता है। कहा भी गया है कि ''शिक्षा बालक को नये–नये अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियाँ तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर, योग्यतानुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें।[9] अतः कहा जा सकता है कि भारत की उच्च शिक्षा में शैक्षिक तकनीकीकरण एक वरदान स्वरुप है जिससे नवीन एवं उत्तम विकास सम्भव है।

9 Kulshrestha, S.P. : Educational Psychology.

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा की उपादेयता

देवराज शुक्ला
सहायक आचार्य
शिक्षाशास्त्र विभाग
कमला नेहरू पी0 जी0 कॉलेज
तेजगाँव, रायबरेली

उच्च शिक्षा का सामान्य अर्थ है– सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशद तथा शुक्ष्म शिक्षाद्य यह शिक्षा उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिवरल आर्ट कालेजो एवम् प्रौद्योगिकी संस्थानो आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तीसरा स्तर है जो प्रायः ऐच्छिक होता है इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण आदि आते है।

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तृतीय विशालतम तंत्र है विगत 64 वर्षो में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या 11.6 गुना, महाविद्यालयों की संख्या 12.5 गुना जबकि छात्रों व शिक्षकों की संख्या में क्रमशः 60 गुना व 25 गुना की बृद्धि दिखाई पड़ रही है।सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में विशेष बृद्धि हुई है और साथ ही उच्च शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी तद्नुरूप बढ़ा है।

वर्तमान मे उच्च शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि भले ही संतोषप्रद प्रतीत हो रही हो पर गुणात्मक उन्नति अभी भी शेष है इस हेतु अखिल भारतीय स्तर पर सुधार हेतु कुछ विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओ मे अकादमिक सुधार के उद्देश्य से शिक्षक, छात्र, शिक्षाकार्मिक,शिक्षाविद् और जनसाधारण से सुझाव मांगे हैं इसके तहत शिक्षा के विभिन्न पक्षकारों से परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य भारत में अनुसरण किए जा सकने योग्य परीक्षा प्रणाली के माडल तथा परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित संरचनात्मक एवं प्रमापीगत परिवर्तन के बारे में राय मांगी गयी हैं द्य दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की स्थापना कर उच्च शिक्षा की गुणात्मकता हेतु भी प्रयास किए जा रहें हैं | NAAC का उद्देश्य 'भारत में स्वमूल्यांकन एवं बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन के सामंजस्य' के जरिये उच्च क्षिक्षा की गुणवत्ता और विशिष्टताओं की जांच करना है परिषद 4708 उच्च शिक्षा संस्थाओ (27.8.18 तक) का मूल्यांकन एवं प्रत्यानन कर चुकी है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए अब भी हमारे देश में विद्यार्थियों को छोटी कक्षा से ही विषय वस्तु का भण्डार भर दिया जाता है उसके पास अन्य किसी कार्य या सोंच के लिए समय नहीं बचता साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओ का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि वह कुछ और नहीं कर पाताद्य अतः अब सरकार को चाहिए कि कक्षा 12 तक की शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा तैयारी का वर्ष मान कर विद्यार्थियों में समीक्षात्मक क्षमता, आलोचनात्मक सोंच शोध जैसे गुणों की व्यवस्था करें जो उनकी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता ला सके, इसी से उनकी आगे की ज़िंदगी सफल और सार्थक बन सकेगी।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा की संभावित चुनौतियाँ

सदन सिंह
सहायक प्राध्यापक
शिक्षाशास्त्र विभाग
कमला नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
तेजगाँव, रायबरेली

प्राचीन काल मे भारतीय मनीषियों ने सा विद्यां या विमुक्तए कहकर शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था इसका महत्व इतना अधिक था कि इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया – ज्ञानं मनुजस्य तृतीय नेत्रंघ्शिक्षा अज्ञानता से, असंतुलन से, मानसिक परवशता से और असत्य से मुक्त करती है। वह स्वावलंबन और स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त करती है तथा अंतर्निहित गुणों को ऊर्ध्वमुखी बनाती है अतः शिक्षा जीवन–निर्माण, मानव–निर्माण और चरित्र–निर्माण की प्रक्रिया है। नैतिकता और सदाचार के बिना चरित्र निर्माण संभव नही है और चरित्र निर्माण ही मानवता का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट ने लिखा है– "शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास है।" उपनिषद में 'आत्मानं विद्धि' पर ज़ोर दिया गया है आत्म ज्ञान शून्य मनुष्य जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकता। महात्मा गाँधी भी स्वीकार करते हैं कि सर्वज्ञ और आत्मसंयमी शिक्षक ही विद्यार्थी के अंतर्निहित गुणो की सही पहचान कर सुषुप्त शक्तियों को वहिर्मुखी बनाता है ।

आज उच्च शिक्षा में इन सारी संभावनाओं को नेपथ्य में डाल दिया है ।शिक्षा का सामाजिक ताना–बाना इस तरह बिखर गया है कि वह मात्र घोर प्रतिस्पर्धी बाजार बनकर रह गया है। जहाँ येन केन प्रकारेण नकल के माध्यम से ही अधिकतम अंक प्राप्त करना ही उद्देश्य हो गया है। ऐसे में जीवन का निर्माण स्वप्न बन गया है। मानव निर्माण और चरित्र निर्माण कि कल्पना ही बेमानी है। शिक्षा संस्थाओं की स्थिति बदतर है और अध्ययन–अध्यापन पटरी से उतरा है। न्यूनतम मानदेय पर अर्द्धशिक्षित और संस्कारहीन प्रबंधतंत्र की सामंती कार्य शैली से नित्य अपमानित होकर बेरोजगार सुयोग्य क्षिक्षक कार्य करने को अभिशप्त हैं। निजी विद्यालयों का अधिकांश वातावरण क्षिक्षक और शिक्षार्थियों के शोषण का जीवंत उदाहरण है ।

स्ववित्तपोषी महाविद्यालय का शिक्षक समाज का सर्वाधिक निरीह प्राणी होता है । न्यूनतम और अनियमित मानदेय पर हाड़ तोड़ मेहनत, निरन्तर फटकार और जिल्लत भरी जिंदगी जीने की मजबूरी, प्रबंधतंत्र के अनपढ़ असहलाधारी गुर्गो की छत्रछाया में उनके द्वारा विकसित की गई भ्रष्ट व्यवस्था में साँस लेने की लाचारी, दहशतजदा मनमानी उगाही की बदौलत उन्मुक्त नकल आधारित परीक्षा में सामूहिक उत्तीर्ण कराने की जवाबदेही, कैरियर की अनिश्चितता और रोजी–रोटी छिनने की आंशका से भयाक्रांत दिनचर्या, न्यूनतम सम्मान के हक से भी वंचित रहकर स्वाभिमान की जगह अनन्त अपमान के घूँट पीते रहकर मूकदर्शक और हतास श्रोता की ईमानदार भूमिका का निर्वहन उनकी स्थायी नियति बन जाती है । एक विकृत दर्पण में वह अपने ईश्वर प्रदत्त निष्कलंक सुन्दर चेहरे का विकृत कर दिया अक्स देखता है और अपने मनुष्य होने की मर्मान्तक पीड़ा से कराहते हुए सर पटक देता है । व्यवसायीकरण के इस वातावरण

में शिक्षा का समग्र उद्देश्य ही तिरोहित कर दिया है । नैतिकता और संस्कार की पुर्नप्रतिष्ठा ही आज की सर्वाधिक जटिल चुनौती है।

ठेके पर नक़ल कराने से उत्तर पुस्तिकाओं का सामान्यीकरण तो होता ही है परीक्षार्थियों की संख्या में बेहतर वृध्दि भी दर्ज होती है । परीक्षकों के लिए भी काफी सहूलियत हो जाती है उन्हें एकाध उत्तर पुस्तिकाएं पढ़कर शेष पुनरावृत्तियों को बिना पढ़े ही अंक देने की प्रतिस्पर्धा में औरों से अधिक मूल्यांकन कर लेने की सद्प्रेरणा प्राप्त होती है और वे चार पाँचघन्टे में ही तीन–चार सौ तक उत्तर पुस्तिकाएं निपटा देते है । अधिकाधिक आर्थिक लाभ के लोभ में कुछ नकल विहीन प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों के हितों की बलि को अन्याय की श्रेणी से मुक्त मान लिया जाता है । सांस्कृतिक अधोपतन के इस दौर में एक हृदयहीन चतुर परीक्षक अपसंस्कृत के आधुनिक खेल में छिपने में कामयाब हो जाता है और इसी के माध्यम से अपने ऊपर बलात्चढ़ाई गई प्रबंधत्रंतीय बेइंसाफी और घृणा की परतें उतार कर मूल्यांकन के बहाने ही सही, समाज से अपना प्रतिशोध लेकर थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है ।

महात्मा गाँधी शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण का विज्ञान मानकर सर्वांगीण विकास पर बल देते है'। यह तभी संभव होगा जब शिक्षा को व्यवसायीकरण से मुक्त कर समाज निर्माण के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी भूमि पर बीज को सही तरह से उगाने की पद्धति विकसित की जायेगी। एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है – "वृक्ष का अंकुर जिस प्रकार झुक जाता है, वृक्ष भी उसी प्रकार झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा जिस प्रकार मानवमन को मोड़ती है , मानव उधर ही मुड़ जाता है ।"

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

प्रगतिशील भारत मे शिक्षा का बदलता परिदृश्य

अन्जू अवस्थी
प्रवक्ता
ब्रहस्पति डिग्री पी0जी0 कॉलेज
कानपुर

शिक्षा चेतना दर्शन और मानवीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति के सर्वग्य विकास के लिये निरन्तर जुडी चली आ रही है। प्राचीन काल मे हम देखें तब शिक्षा का उतना महात्व नही था, व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतुश्ट था, परन्तु बदलते परिवेश के साथ शिक्षा मनुष्य की आदि और अनंत बनती चली गयी। क्योंकि हमेषा से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुश्य को पूर्णता प्रकट करना रहा हैं।

प्राचीन काल मे ज्ञान देने के कार्य मे शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण था वह किसी विषेश क्षेत्र मे विषिश्टता प्राप्त किए होता था। अति प्राचीन काल मे गुरूजन शिक्षा के जरिये राजकुमारो को युद्ध मे पारंगत बनाते थे। बदलते हुऐ परिवेष मे वह शिक्षा के जरिये विद्यार्थी मे जीवकोपार्जन की क्षमता प्रदान करने लगे, परन्तु अब व्यक्ति और समाज का रूप बदल जाने के कारण शिक्षा का रूप अधिक विकसित हो गया है और शिक्षा का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। अब शिक्षक का कार्य किसी विषेश विशय पर पारंगत करना नही होता, अपितु उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा भावात्मक विकास करना भी है व उसे समाज या राश्ट्र का उत्तम एवं उपयोगी नागरिक बनाता है। ''शिक्षा का मूलभूत उद्धेष्य यही है।'' बदलते हुए समय के साथ यदि हम समाज को देखे तो मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं मे मुद्रा का विषेश स्थान है। प्रतियोगिता के युग मे मानव जीवन की अधिकाष क्रियाएँ मुद्रा से प्रारम्भ होकर मुद्रा मे ही अंत हो जाती है। समय के साथ साथ मानव ने हर क्षेत्र मे विकास किया है और आज आधुनिक युग को यदि अर्थयुग कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

एक लम्बे समय से शिक्षा प्रणाली वेतनवद है। वर्तमान समय मे शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय की भांति ज्ञान परख उपक्रम ही नहीं वरन उसके प्रादायक साधानों एवं शिक्षकों के वेतन और आय के स्त्रोत से भी संबन्धित है।

निश्चित ही ऐसे संदर्भ मे शिक्षक मात्र वेतन भोगी कर्मचारी बनकर रह गए है। अतः अच्छी शिक्षा के लिये शिक्षकों के वेतन से व्युत्पन्न व्यय और बचत की प्रवृत्तियों का आर्थिक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन, मध्य आधुनिक काल हम जिस पर निगाह डाले शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करना रहा है। परन्तु वर्तमान युग मे औद्योगिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जिस कारण से सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से काम नही चलेगा, बल्कि उस शिक्षा की आवश्यकता है । जिससे की व्यक्ति स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके।

देश के अतीत पर नजर डाले तो आजादी की लड़ाई को उग्र रूप देने वाला ''शिक्षक वर्ग'' ही था और लड़ाई पूरी शिक्षा के मंदिरों से (काशी विद्यापीठ, षान्ति निकेतन) से ही लड़ी गयी थी और जब एक बड़ा वर्ग छुआछूत व जातिवाद की वजह से समाज मे हेय नजर से देखा गया तो उसे शिक्षा (आरक्षण) ने ही उभारा था। वर्तमान काल भी इस बात का साक्षी है कि बिना शिक्षा के सभ्य समाज की कल्पना भी

संभव नही है। वस्तुतः शिक्षा ही समाजिक परिवर्तन का सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। शिक्षा द्वारा ही समाज मे वास्तविक परिवर्तन होता है और वह इसे आधुनिक बनाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वतन्त्रता के बाद विश्वविद्यालयों मे उच्च शिक्षा व प्रावाधिक शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है। परन्तु प्राथमिक शिक्षा का आधार दुर्बल होता चला गया। शिक्षा का लक्ष्य राश्ट्रीयता, चरित्र निमार्ण व मानव संसाधन विकास के स्थान पर मशीनीकरण रहा जिससे 40 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों का देश से बाहर पलायन जारी रहा।

देश मे प्रौढ़ शिक्षा और साक्षारता के नाम पर लूट–खसोट प्राथमिक शिक्षा का दुर्बल आधार, उच्च शिक्षण संस्थानो का अपनी सशक्त भूमिका से अलग हटना तथा अध्यापकों का पेशेवर दृश्टिकोण, वर्तमान शिक्षा प्राणाली के लिए एक नया संकट उत्पन्न कर रहा है।

इस प्रकार सामाजिक संरचना से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सम्बन्धों, पाठ्यक्रमों का गहन विष्लेशण तथा इसकी मूलभूत दुर्बलताओं का गंभीर रूप से विष्लेशण की चेष्टा न होने के कारण भारत की वर्तमान शिक्षा प्राणाली आज भी संकटों के चक्रव्यूह मे घिरी हुई है। प्रत्येक दस वर्षों में पाठ्य–पुस्तकें बदल दी जाती हैं जबकि शिक्षा का मूलभूत स्वरूप परिवर्तित कर इसे रोजगारोन्मुखी बनाने कि आवश्यकता है।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्राणाली गैर तकनीकि छात्र–छात्राओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो अंततोगत्वा अपने परिवार व समाज पर बोक्ष बन कर रह गयी है। अतः शिक्षा को राश्ट्र निर्माण व चरित्र निर्माण से जोडने की नितान्त आवश्यकता है।

परन्तु हाल मे ही दो चौंकानी वाली खबरें सामने आयी पहली भारत मे स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले 22 करोड़ विद्यार्थियों मे से केवल 1.60 करोड़ विद्यार्थी ही कालेजों में दाखिला लेते है। दूसरी ओर देश भर के 30 लाख विधार्थियों में से केवल 10 प्रतिशत ही अच्छी नौकरी पाने के येाग्य होते है। आंकड़ों को हम नजरंदाज नहीं कर सकते। सवा अरब की आबादी वाले हमारे देश के स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में से केवल एक प्रतिशत ही अच्छी नौकरियों के हकदार हैंघ् बाकी 99 प्रतिशत के लिय तो तेजी से बदलते रोजगार परिदृश्य मे अवसर घटते ही जा रहे है और इसके लिये सिर्फ शिक्षातन्त्र जिम्मदार हो जो लगातार बदलती शिक्षा के प्राणाली के बावजूद रोजगारोन्मुखी नहीं हो पाया है। वर्तमान मे सरकार को इस पर विचार करने एवं जल्द से जल्द इसका समाधान ढूँढने की आवश्यकता है।

शिक्षातन्त्र को स्कूलों से ही सुधार करने की आवश्यकता है। पढ़ाई केवल क्लास पास करने या डिग्री सर्टिफिकेट लेने का माध्यम नही है, विद्यार्थियों मे विशयों को समझने का नजरिया पैदा करना सीखना होना चाहिए। उनमें किताबों के बाहर का व्यावहारिक ज्ञान भरना होगा क्योंकि जो विद्यार्थी डेढ़ दषक से ज्यादा तक स्कूल कॉलेजों मे पढ़ाई करता है। वह उसके बाद अच्छा रोजगार पाकर सुंदर जीवन जीने का सपना भी देखता हैं। यह सपना पूरा करना भी हमारे शिक्षा संस्थानों का दायित्व होना चाहिए।

इसके लिए समूची शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा संस्थानो को रोजगार,उधमिता, विकास और ज्ञान व समृद्धि निर्मि गुणो को विकसित करने मे सक्षम होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *मालती सारस्वत–भारतीय शिक्षा की व्यवस्था व समस्यायें*
2. *श्री रमन बिहारी लाल–भारतीय शिक्षा का विकास और समस्या*
3. *एस.अबीद.अली–भारतीय संस्कृति*

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

वैदिक वाङ्मय में वर्णित उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति

संध्या ठाकुर
प्रवक्ता
संस्कृत विभाग
कानपुर विद्या मंदिर महिला पी0 जी0 महाविद्यालय
स्वरूप नगर कानपुर

किसी देश की उन्नतिका आधार शिक्षा है। शिक्षित राष्ट्र का निर्माण समाज, और परिवार के द्वारा संभव होता है। समाज की प्रगति एवे संस्कृति को शिक्षा के द्वारा ही दिशा प्रदान की जा सकती है । उस देश की समृद्धि एवं बौद्धिक क्षमता का आंकलन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करता है। जीवन को आनंदमय एवं सुखमय करता है। व्यक्तिगत समस्यायें शारिरिक मानसिक चारित्रिक, आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा के महत्व को आधुनिक युग में ही स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि शिक्षा आदिकाल से ही विभिन्न रूपों में विद्यमान एवं महत्वपूर्ण थी। वैदिक एवं पूर्व वैदिक काल में भी शिक्षा, उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी आज है। परन्तु वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में शिक्षा सर्व सुलभ नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, राजाओं, राजपुत्रों एवं समाज के प्रभावशाली लोगों की संतानों को ही प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था के रहते शिक्षा–दीक्षा एवं व्यवसाय के क्षेत्र निर्धारित थे। शिक्षा एवं व्यापार का अधिकार निश्चित परिधि में बंधा था। आधुनिक युग के समान शिक्षण–संस्थानों की जगह ऋषि मुनियों के आश्रम गुरूकुल एवं देवालय ही शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। शिक्षा के उद्देश्य भी सीमित थे। राजाओं शासकों एवं राज परिवार के लोगों को शास्त्र शस्त्र, राजनीति तथा शासन चलाने के गुर सिखाना ही शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। आश्रमों एवं गुरूकुलों को शासक वर्ग का संरक्षण एवं प्रश्रय प्राप्त होता था। गुरू विशेष सम्मान के पात्र होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा नहीं होता था। राजनैतिक हस्तक्षेप भी नहीं होता था। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि माध्यमिक के पश्चात ही उच्च शिक्षा प्रारंभ होता है। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वे समस्त संस्थायें हैं जिनका विकसित स्तर है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान आदि।

शिक्षा शब्द का व्युतपतिलभ्य अर्थ है सीखना। सीखने और सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा वर्चस्व रहा है। हमारे धर्मग्रंथ इसके प्रमाणस्वरूप हैं किन्तु आज भारत जैसे विकासशील देश में उच्चशिक्षा की दशा अत्यंत शोचनीय है। हमारे वेद प्रमाणित करते है कि वैदिक कालीन शिक्षा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे यहाँ गुरूकुल शिक्षा की परंपरा का निर्वहन किया जाता था। गुरू के द्वारा शिष्य को उपदिष्ट करना ही हमारी शिक्षण प्रणाली थी। हमारे उपनिषद् इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला विश्वविद्यालय का समृद्ध होना भी इसी के प्रमाण स्वरूप है। आज उच्च शिक्षा सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार बन रही है। शिक्षण संस्थान तो बहुत हैं पर योग्य शिक्षकों का न होना प्राइवेट संस्थाओं की होड़ आदि कारण है।

आदिकाल से ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारी धारणा रही है कि "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात विद्या वह है जो कि व्यक्ति की क्षमता को संकुचित दायरे से निकालती है एवं उसकी चेतना को अज्ञान, ईर्ष्या और संकीर्णता से मुक्त करके उसे उदात्त बनाती है और ज्ञान व्यक्ति की उर्जा को केन्द्रित करके उसे और अधिक क्षमतावान तो बनाता ही है साथ ही वह उसे जटिल जगत से निकालकर सत्य के दर्शन भी कराता है। "शास्त्र प्रयोजनम् तत्व दर्शनम" शास्त्र का प्रयोजन ज्ञान का उद्देश्य सत्य से परिचित कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी प्रदेश जाति अथवा समुदाय के लिए न होकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए होती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि स्वतंत्र भारत में आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण नहीं हो सका है। इसका मूल कारण शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा समाज की इस विषय पर उदासीनता है। जगद्गुरू आदि शंकराचार्य जब दिग्विजय के प्रसंग में मण्डन मिश्र से मिलने मिथला (वनगाँव) जो बिहार में पड़ता है पहुँचे तो उनका घर पूछने पर मार्ग पर जाती हुई एक दासी ने जो उत्तर दिया था वह स्मरणीय है–

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरीटाङना यत्र गिरोगिरन्ति।
शिष्यैरसंख्यैरभि मिधीयमान आवेहि तन्मंडन मिश्र धाम।। – 3

अर्थात् पिंजड़ों में बैठे हुए तोता, मैना जहाँ वेद स्वतः प्रमाण है अर्थात परतः प्रमाण है, इस गूढ़ विषयों पर चर्चा करते हो तथा जहाँ असंख्य शिक्षक इन गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श कर रहें है। उसे ही आप मण्डन मिश्र का निवास समझें। किसी से पूंछने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग भी जहॉ इतना जागरूक होता है वहाँ शिक्षा एवं संस्कृति का समग्र विकास अपने आप होता रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से भारतीय शिक्षा नीति स्पष्ट होती है। जहाँ के पशु–पक्षी भी सुशिक्षित होकर वेदाध्ययन करते थे। हमें अपने देश की प्राचीन शिक्षा नीति पर गर्वान्वित होना चाहिए और प्रेरित होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए।

हमारा वेद समस्त उच्चतम ज्ञानकोष का श्रोत है। ऋग्वेद हमें भौतिक वातावरण से दूर रहकर परम शान्ति के लिए अन्तर्मुखी प्रकृति अपनाने का संदेश देता है। वैदिक काल में आज की भाँति मुद्रण यंत्र न था पुस्तक न थी, बड़े–बड़े विद्यालय न थे किन्तु तप की साधना थी, गुरू का मुख और शिष्य के कर्ण थे। केवल बुद्धि को मेधावी बनाने के लिए ही प्रार्थनायें नहीं की जाती थी अपितु उस बुद्धि को पवित्र एवं कालुष्य रहित बनाने के लिए भी की जाती थी। वैदिक ऋषि इसी आदर्श को हृदयंगम कर अपने शक्तियों के विकास के लिए ईश्वर से प्रातः सायं प्रार्थना किया करते थे–

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान ।
युयोध्यस्मज्जु हुराणमेनो भूयिष्ठान्ने नमः उक्तिं विधेम् ।। – 4

हे ईश्वर हमारी बुद्धि को सद्मार्ग से विश्व में ले चले, ले ही नहीं चलें अपितु आप हमारे हृदय से दुर्गुण एवं पाप भावनाओं को निकाल कर निष्पाप एवं शुद्ध पवित्र बुद्धि प्रदान करें, इसके लिए हम पुनः पुनः आपकी प्रार्थना करते है–

यां मेधां देवगणाः पिपरश्चोपाराते ।
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरू ।। – 5

वैदिक ऋषि पवित्र भाव भूमि पर स्थित होकर पुनः बुद्धि को मेधावी बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है–

तेजोऽसि तेजार्माय धेहि वीर्यमसि वर्य मयि धेहि।
बलमसि बल मयि धेहि, सहोसि सहो मयि धेहि।। – 6

उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में समस्त विषयों के पाठ्यक्रमों को आधुनिक जीवन के अनुरूप व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में हमारे मानवीय सामाजिक मूल्य एवं आदर्श को आदर्श रूप में रखना

चाहिए। पाठ्यक्रम में सामाजिक विषय को सम्मिलित करना चाहिए। रोजगार परक शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण प्रणाली आधुनिक है इसके लिए शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण विधियों में व्याख्यान के साथ आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा व्यवस्था में आज भी वही घिसी–पिटी परीक्षा प्रणाली चल रही है। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य इतनी लम्बी और अविश्वसनीय परीक्षा प्रणाली को जड़ से बदलना आवश्यक है। परीक्षा प्रणाली आधुनिकतम तकनीक पर आधारित हो। परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद ही परिणाम सामने हो। प्रत्येक कॉलेज को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जाये और अध्यापकों को भी पावर प्वाइंट कक्षा के लिए प्रेरित करने चाहिए। जब शिक्षक नूतन प्रणाली को प्रस्तुत करेंगें तभी छात्र उसे ग्रहण कर सकेंगें। शोध की गुणवत्ता पर भी चिन्तन की महती आवश्यकता है। हमारे धर्मग्रन्थ में अत्यंत संक्षिप्त एवं सारगर्भित शब्द का व्यक्त है –

विद्या ददाति विनियम् विनयात् ददाति पात्रताम् ।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात्धर्मम् ततः सुखम् ।। – 7

अतः उच्च शिक्षा में मानव का सर्वाडीण विकास उसके अनुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण से जोड़कर ही संभव है शिक्षण–प्रशिक्षण के द्वारा ही हम विश्व दृष्टि में सुदृढ़ हो सकते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम अत्याधिक रोचक हों, शिक्षक छात्रों को उन पाठ्यक्रमों को समझाने के लिए नये नये व्यवहारिक तरीके अपनायें ताकि छात्रों का उच्च स्तरीय बहुमुखी विकास संभव हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत में उच्च शिक्षा – डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव
2. भारतीय संस्कृति – राज किशोर सिंह
3. वैदिक साहित्य का इतिहास
4. यजुर्वेद – 40/16
5. यजुर्वेद – 32/14
6. शुक्ल यजुर्वेद – 19/9
7. निति शतकम् –

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

स्वावित्त पोषित महाविद्यालय की समस्यायें एवं चुनौतियाँ

आदित्य सक्सैना

किसी भी समाज का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। शिक्षा ही है जो समाज के नागरिकों को ज्ञान, चरित्र तथा नैतिकता प्रदान करती है। भारतीय शिक्षा का अपना बहुत पुराना इतिहास है, शिक्षा को प्रकाष का स्त्रोत माना गया है तथा यह जीवन के विभिन्न कार्यों में हमारा मार्ग अलोकित करती हैं। शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है।

प्राचीनकाल में शिक्षा व्यवस्था राजा और ऋषि मुनियों के मार्गदर्शानुसार चलती थी। वर्तमान समय में यह निजी एवं सरकारी प्रयासों से प्रदान की जा रही है, सरकारी शिक्षा राज्य तथा केन्द्र सरकार के अनुदान पर संचालित होती है एवं निजी शिक्षा व्यवस्था स्थानीय प्रबन्धकों द्वारा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था पूर्णतः वित्त विहीन प्रयासों से चलती है। यहां किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है, प्रबन्धक स्वयं ही अपने खर्चों का वहन करते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बाद तृतीय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा उच्च शिक्षा कहलाती है। भारत में यह विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है। शिक्षा का तीव्र गति से विकास करने हेतु सन 2007 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रौदा जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 1500 विश्वविद्यालयों एवं 35000 महाविद्यालयों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के आधार पर सरकारी एवं निजी प्रयासों से महाविद्यालय खुलने लगे हैं। सर्वप्रथम सन् 1996 से निजी क्षेत्र में स्वावित्तपोषित महाविद्यालय खोलने की अनुमति मिली और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने लगी। यह शिक्षा को गति देने का एक संख्यात्मक वृद्धि वाला प्रयास था। इसका दूसरा पक्ष शिक्षा की गुमणात्मक वृद्धि भी आवश्यक थी। विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान कर दी, चूंकि इन स्वावित्तपोषित महाविद्यालयों को किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता था। इसलिए इनके प्रबन्धक संस्थान के संचालन में मनमानी करने लगे और यह स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक समस्या एवं चुनौती बन गये। यह मानकों के अनुरूप गुणवता प्रदान करने में असमर्थ रहे। इसका मुख्य कारण था, वित्त का अभाव प्ररम्भ में प्रबन्धकों ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया कुछ समय के बाद उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप लाभ नहीं मिला जिसके कारण उन्हें बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ऐसे में उनके द्वारा ऐसे रास्ते अपनाये गये जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। आज स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में समस्याओं और चुनौतियों का अम्बार लगा हुआ है। भारत एक ओर तो जहाँ विकास की ऊचाईयाँ छूने को तैयार हैं। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है और आज विश्वविद्यालय नैक (NAAC) कराने की बात कर रहे हैं। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय नैक से बचने के रास्ते ढूढ़ रहे हैं। कुछ महाविद्यालयों ने नैक के समय तो अपने आपको ठीक कर लिया

इसके पश्चात् वह अपनी पुरानी व्यवस्था में आ गये आज स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में निम्न समस्यायें और चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। इन पर विचार करना आवश्यक है –

1. शिक्षकों से सम्बन्धित
2. छात्रों से सम्बन्धित
3. वित्त से सम्बन्धित
4. पठ्न–पाठन सामग्री से सम्बन्धित
5. प्रबन्धकों से सम्बन्धित

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों की समस्या बड़ी चुनौतीपूर्ण है। जिसका समाधान उतना सरल नहीं है, जितना दिखाई देता है। प्रबन्धकों को जब अपने लाभ में कमी दिखाई दी उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षकों की संख्या में कमी कर दी। पहले जहां वह मानकों के अनुरूप शिक्षक रखते थे वहीं अब मानक कागजों आ गये और उपस्थित शिक्षकों की संख्या 1 या 2 हो गयी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य शिक्षकों को रखा जाने लगा। जो नाम मात्र के वेतन पर थे और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी उनके मानकों के अनुरूप नही थी। यही शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर अनुमोदित शिक्षकों के हस्ताक्षर भी करते है। अनुमोदित शिक्षक अब शिक्षण कार्य न करके अपने व्यक्तिगत कार्य या विभिन्न विद्यालयों में अनुमोदन करते हुए दिखाई देते है। प्रबन्धक ऐसे शिक्षकों को वर्ष भर के लिये कुछ धनराषि देते हैं और अपने महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों से अनुमोदन करवा लेते हैं। यह हमारी वर्तमान शिक्षक व्यवस्था है जिसमें हमारे देश के निर्माता और प्रबन्धक तंत्र दोनों ही प्रषन्नता का अनुभव कर रहे हैं। स्वावित्तपोषित महाविद्यालयों में अभी भी अनुमोदित शिक्षकों की आवश्यकता होने पर उन्हें कुछ खर्चा पानी देकर बुलाया जाता है। जांच टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा जांच टीम के जाते ही शिक्षकों को ससम्मान लिफाफा देकर विदा कर दिया जाता है। सोंचने का विषय है जांचकर्ता तथा विश्वविद्यालय भी इस व्यवस्था से परिचित है। वह यह सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं करते हैं। उनके ऊपर कोई दबाव आ जाता है या उनका लिफाफा प्रेम ऐसा करने नहीं देता है।

आप देख सकते हैं कि वास्तविक प्राचार्य अपनी कुर्सी पर कभी नहीं मिलेगें, वह किसी और महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे होते हैं। प्राचार्य की कुर्सी पर प्रबन्ध तंत्र का वफादार आदमी या स्वयं प्रबन्धक महोदय ही मिलते हैं। अब जिस महाविद्यालय में शिक्षक कार्य करना नहीं चाहते हैं। वह कक्षा में जाकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक या दो विद्यार्थी आने पर उन्हें भगा दिया जाता है। शिक्षण वहीं परम्परागत है वैज्ञानिक तकनीकों, विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, छात्र व्यवस्था से ऊबकर स्वयं ही भाग जाते हैं। उनके जाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस व्यवस्था से गुणवत्ता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यह समस्या एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है इसका समाधान भी हम और आप ही कर सकते है। क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है, जिस पर इमानदारी से प्रयास किया जाये तो वह दूर न हो।

मेरे विचार से सर्वप्रथम शिक्षकों को अपनी सोंच बदलनी चाहिये कि वह महाविद्यालयों में सिर्फ कागजों में उपस्थित रह कर शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें शिक्षकों में एकता की कमी है वे अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने साथियों का ही अहित करते हैं। वह अपनों के शोषण करके षिकार स्वयं बनते हैं। यदि हम सभी एक जुट होकर अपनी बात प्रषासन से करेगें तो सुधार अवष्य होगा। जब हम पैसों के लिए वर्ष भर नाम चलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कही न कही एक ऐसा शिक्षक जो पढ़ाना चाहता है उसका अहित होता है। वह राष्ट्र को अपनी सेवायें नहीं दे पाता है। यदि शिक्षक नाम चलाने की

शर्त पर तैयार नहीं होंगे तो देखियेगा एक दिन प्रबन्धक शिक्षकों के पीछे घूमेगें और कागजों में नाम चलने की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

विश्वविद्यालयों को भी इस हेतु सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। यदि शिक्षकों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि को विश्वविद्यालयों की बेबसाइड पर ऑनलाइन कर दिया जाये तो शिक्षकों का एक से अधिक विश्वविद्यालयों में अनुमोदन करना सम्भव नहीं होगा। इस पर बहुत से विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं और इस व्यवस्था पर कुछ सीमा तक अंकुष भी लगा है। इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमे एक जुट होने की, अपनी सोच में बदलाव लाने की और विश्वविद्यालय द्वारा इस दिषा में कठोर एवं सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या बड़ी चुनौती पूर्ण है, आप ज्यादातर महाविद्यालयों में सीटें खाली रह जाती हैं, ऐसे में प्रबन्धतंत्र की मनमानी देखने को मिलती है। आज महाविद्यालयों में शिक्षार्थी प्रवेष नहीं ले रहे हैं। शिक्षार्थी परिक्षार्थी बन गये हैं। उसमें प्रवेष के समय ही कह दिया जाता है कि सिर्फ परीक्षा के समय आईयेगा आपको वर्ष भर नहीं बुलाया जायेगा। गृहकार्य के लिए फोटो कापी दे दी जायेगी। उसे खाली डायरी में उतार लाना महाविद्यालय में कभी आवश्यकता होगी तो आपकों फोन कर दिया जायेगा आप सम्पर्क में रहियेगा। इण्टरशिप की चिन्ता मत करना सब करवा देगें। यह संवाद कह कर महविद्यालय अपनी सीटों को भर रहे हैं। बहुत से प्रबन्धक दलालों के माध्यम से प्रवेष लेते हैं, कुछ छात्रों को पांच–दस हजार रूपये देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज समाज के समक्ष यह समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रषासन को नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय को भी इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिये। प्रवेष सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाये जो महाविद्यालय में प्रतिदिन अध्ययन हेतु आ सके। ऐसे छात्र जिनकी उपस्थिति मानकों के अनुरूप नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाये उन्हें परीक्षा से वंचित किया जाये उनके ऊपर कुछ आर्थिक दण्ड लगाये जायें। उनके मात–पिता से विचार विमर्ष कर उन्हे वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाये। विभिन्न महाविद्यालयों से छात्रों से सुविधा शुल्क लेकर उन्हें इच्छानुसार अवकाष प्रदान कर दिया जाता है, बहुत से महाविद्यालयों में छात्रों से मनमानी धनराषि वसूल की जाती है, इन सभी व्यवस्थाओं के प्रति चिंतन, शोध और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तभी इस समस्या का निदान हो पायेगा।

स्वावित्तपोषित महाविद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या धन की होती है, जोकि एक चुनौती के रूप में सदैव सामने खड़ी रही है। इसके लिए प्रबन्धक महाविद्यालयों में मनमानी करते हैं। छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। शिक्षकों को नाम मात्र का वेतन दिया जाता है। अनुमोदित शिक्षकों की जगह गैर अनुमोदित शिक्षकों को रखा जाता है। कम शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है, प्रबन्ध तंत्र अनुमोदित शिक्षकों के बैंक खाते खुलवाकर पासबुक, चैकबुक एवं ए0टी0एम0 कार्ड स्वयं रख लेते हैं तथा खातों का संचालन भी स्वयं करते हैं। ज्यादातर शिक्षकों को अपना खाता नम्बर भी नहीं पता होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों को पहल करने की आवश्यकता है, यदि विश्वविद्यालय वेतन देने वाली धनराषि को स्वयं अपने पास जमा कर ले और हर माह उनके खातों में जमा करा दे तो काफी हद तक इस समस्या से निदान मिल सकता है। जो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय नियमानुसार कार्य कर रहे हैं उन्हे सरकार द्वारा, यू0जी0सी0 द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तरह समस्या पर कुछ नियंत्रण सम्भव हो सकता है।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पठन–पाठन सामग्री का भी अभाव है, प्रबन्धक पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं करते हैं। जहां पुस्तकालय है वहां पुस्तकें नहीं मगाई जाती हैं। कहीं–कहीं पर पुस्तकें है, वो

छात्रों को दी नहीं जाती हैं क्योंकि पुस्तकें देने से फटने, खोने या गन्दी होने का भय रहता है। यही व्यवस्था प्रयोगषालाओं के साथ होती है, वहां पर्याप्त प्रयोग हेतु समान नहीं होता है। प्रयोगषालायें वर्ष भर बन्द रहती है उन्हें विषेष अवसरों या जांच आदि के समय ही खोला जाता है। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रोजेक्टर एवं अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे छात्र निरस्ता का अनुभव करते हैं। वह स्वतः ही कक्षा छोड कर चले जाते हैं, छात्र संख्या कम होने पर उन्हें भगा दिया जाता है। कहीं–कहीं पर एक ही शिक्षक विभिन्न विषयों का अध्यापन कार्य करता है। जहां विद्यार्थी एक ही शिक्षक के दर्षन करे ऊब जाता है। यह समस्या भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि ऐसे शिक्षकों को ही रखा जाये जो अध्ययन–अध्यापन में रूचि रखते हों। विश्वविद्यालय यह सुनिष्चित करें की महाविद्यालय में पर्याप्त संसाधन है कि नहीं है इस हेतु वे आकमस्मिक जांच करें। महाविद्यालय के पूरे दिन की गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग मांगकर देखें छात्र एवं शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज हो। प्रतिवर्ष खरीदे गये संसाधनों की पक्की रषीद विश्वविद्यालयों में देखी जाये, इन सभी प्रयासों से समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

मैंने अन्तिम समस्या के रूप में स्वयं प्रबन्धक को रखा है, आप देख सकते हैं सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय पूँजीपतियों, राजनेताओं या समाज के दबंग व्यक्तियों के हैं। इनके पास पैसा व पावर दोनों है, ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह महाविद्यालयों को अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए और धन कमाने के लिए खोलते हैं। ऐसे में उनके महाविद्यालय में जांच के लिए जाने वाले सदस्य कभी भी सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। प्रषासनिक दबाव बनाकर यह अपने सभी काम करा लेते हैं। इनके विरोध में कभी भी जल्दी कोई आवाज नहीं उठाता है। यह एक ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्या है जिसका निदान असम्भव प्रतीत होता है। फिर भी शिक्षा के एक जुट होकर अपने निजी स्वार्थों का त्याग करके आवाज उठाते हैं, प्रषासन तक अपनी समस्या पहुँचाते हैं। प्रबन्धतंत्र को अपना शोषण करने से रोकते हैं। छात्र भी अपना डिग्री मोह छोडकर वास्तविक स्थिति से प्रषासन को अवगत कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परिर्वतन न हो, प्रबन्ध तंत्र को हम बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रबन्धक बिना शिक्षक और छात्र के महाविद्यालय नहीं चला सकता है यदि हम सब एक जुट होकर अपने सम्मान की बात कहेंगे, हम की बात करेगें और अपनी सोंच बदलेगें तो एक न एक दिन प्रषासन भी हमारा सहयोग करेगा। विश्वविद्यालय कठोर नियम बनायेगें तो शिक्षा में गुणवत्ता स्वतः आ जायेगी। तब शायद हमें किसी गुणवत्ता परीक्षण नैक (NAAC) आदि भी आवश्यकता ना हो।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

अजीत प्रताप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विभाग
एम0एम0के0 (पी0जी0) कालेज
बलरामपुर

भारत में स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्तमान में जो हालात हैं उस पर चिन्ता होना स्वभाविक है। इन संस्थानाओं का स्वरुप तो शिक्षण संस्थान का है लेकिन वास्तों में इनकी कार्य पद्वति शिक्षा (डिग्री) की दुकान जैसी है। वास्तव में इन संस्थानों में डिग्री बेचने का कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में निजी करण से लगभग 2 दशको के भीतर देश भर में निजी कालेज/विश्वविद्यालय की बाढ़ सी आ गयी है, लेकिन ये संस्थान शिक्षा के मूल उद्देश्य को पूरा करने के बजाय धनार्जन के साधन के रुप में सेवा दे रहे हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य प्रदेशों में संचालित ज्यादातर कालेज/विश्वविद्यालय बड़े नेताओं या उद्योगपतियों के हैं जिनका स्वरुप तो शैक्षिक संस्थान का है लेकिन वास्तव में वे शिक्षा उद्योग की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आशय यह है कि इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक कामना है गुणवत्ता विहिन शिक्षा प्रदान करना, अयोग्य शिक्षकों से शिक्षण कार्य करना, छात्र संख्या बढ़ाने हेतु नकल जैसे असामाजिक कार्यों को बढावा देना आदि इन संस्थानों की पहचान बन चुकी है।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि जैस प्रकार की शिक्षा इन संस्थानों में दी जा रही है क्या वह इक्सवीं सदी में जरुरी कौशल हासिल करने में मद्दगार है यह सिर्फ डिग्रीधारी जमात तैयार हो रही है, ग्रामीण इलाको में संचालित इन महाविद्यालयों में निश्चित रुप से युवा पीढी विशेष रुप से लड़कीयो की शिक्षा में मद्दगार साबित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा अगर प्रांसगिक और गुणवत्ता पूर्ण नही होगी तो वह किस काम की अर्थात इन छात्र–छात्राओं का शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वह प्राप्त न हो सकेगा। और इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्र–छात्रायें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को पूर्ण करने में भी अक्षम होंगे।

थाईलेण्ड मलेसिया जैस देशों में अपनी उच्च शिक्षा की नीतियों में बदलाव करते हुए स्वीकार किया है कि उच्च शिक्षा में विस्तार और निवेश आर्थिक समृद्धि लायेगा और इसी बदलाव का परिणाम है कि इन देशों में शिक्षा शिक्षक का अनुपात पहले से बेहतर हुआ है। थाईलैण्ड में एक शिक्षक पहले जहां लगभग 35–40 छात्रों को शिक्षा देते थे आज लगभग 20 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं जबकि भारत के स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में छात्र शिक्षक अनुपात की बात करना बैमानी होगी।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया तो दुनिया के विकसित एवं आर्थिक रुप से समर्थ देश भारतीय छात्रों को आकार्षित करने में सफल रहेंगे। प्रत्यके वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों जाने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह स्थिति तब है जब हमारे देश में स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थानों का जाल स फैला हुआ है, अपने देश में शिक्षा में जो असमानता व्याप्त है वह कौन दूर करेंगा ? अपवादों को छोड़ दे तो अकसर यह देखा

जाता है कि एक मध्यवर्गी, उच्चवर्गी परिवार से सम्बन्धित छात्र–छात्रा एक अच्छे स्कूल में पढ़ते है और फिर अगर सरकारी कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश नही भी मिला तो किसी निजी कालेज/विश्वविद्यालय में 25–50 लाख की मोटी रकम देकर कानून मेडिकल जैसी डिग्री प्राप्त कर लेते है। डिग्री लेने के लिए देश से बाहर जाने का विकल्प तो उनके लिए खुला ही रहता है, प्रश्न यह होता है कि क्या गरीब, किसान, या सामान्य परिवार के छात्र–छात्रा को यह अवसर मिल पाता है ? हमारी शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के सवाल में यह बहस भी शामिल होनी चाहिए।

स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक बात यह भी कटु सत्य है कि वर्तमान में इन संस्थानों में ऐसे शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जाता है जिनसे वास्तव में तो प्राईमरी स्कूलों में भी शिक्षण कार्य कराना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। अर्थात योग्य शिक्षकों की नियुक्त सिर्फ कागजों पर होती है इनके स्थान पर ऐसे अयोग्य शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिया जाता है। यह समस्या यह भी सोचनीय है कि इन संस्थानों में जो योग्य शिक्षक कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन प्रशासनिक पदों पर असीन व्यक्तियों की चाटुकारिता से परहेज करते हैं उन्हें हतोत्साहित कर दिया जाता है और कई प्रकार के भेद–भाव का शिकार होना पड़ता है उन्हें बेवकूफ बताया जाता है और संस्था से निकलवाने के लिए तरह–तरह के हथकडें अपनाये जाते हैं स्ववित्त पोषित संस्थानों में इस तरह की इनेको चुनौतियां विद्यमान है जिस पर गम्भीरता से विचार किये बिना समाधान सिर्फ और सिर्फ दिवास्वपन जैसा प्रतीत होता है।

महान दार्शनिक प्लेटों में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हुए कहा है कि राज्य सर्व प्रथम एक शिक्षण संस्थान है अगर राज्य अपने नागरिकों को उचित और रोजगार परक शिक्षा देने में असमर्थ है तो उस राज्य का विनाश निश्चित है राज्य का मुख्य कार्य नागरिक निर्माण है और यह केवल उचित व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से ही सम्भव है।

एक राज्य के नागरिक अगर चरित्रवान एवं कार्यशील हो तो अच्छे से अच्छे कानून भी प्रासगिंक हो जायेगें। इसके उलट यदि राज्य के नागरिक और शिक्षा व्यवस्था ही भ्रष्ट हो तो कड़े से कड़ा कानून भी उस राज्य को श्रेष्ठ नही बना सकता एक शिक्षक की गलती राष्ट्र के चरित्र में झलकती है और भारत वर्ष इसका अपवाद नही है।

अतः वर्तमान सरकार को चाहिए कि वह स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए इसकी नीतियों में बदलाव के साथ उनके क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाये। इन संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के साथ उनकी सेवा शर्तें, उचित वेतनमान, भविष्य निधि आदि के निर्धारण के साथ इनके कुशल क्रियान्वयन हेतु कठोर कदम उठाये, इन संस्थानों द्वारा वसूल की जाने वाली मोटी रकम पर लगाम लगाने के लिए भी कठोर नीति का निर्धारण करे जिससे यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण भविष्योन्मुखी, नैतिकता पूर्ण एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक शिक्षा प्राप्त हो न की अयोग्य, अविवेकी और बेरोजगारी युक्त छात्रों का समूह निकलकर देश में अराजकता फैलाये।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

शिक्षा का महत्व

अंशु गुप्ता
ब्रहस्पति डिग्री पी0जी0 कॉलेज

शिक्षा वह प्रकाशपुंज है जो सभी को प्रकाशित करता है। शिक्षा के बिना आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । शिक्षा से ही राष्द्र की पहचान होती है । किसी भी राष्द्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है । प्राचीन काल में विद्यार्थी अपने गुरू से उनके अनुभवों तथा उनके अनुदेशों के अनुसार अभ्यास का ज्ञान और कौशल में निपुणता प्राप्त करते थे । शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा में सफल होना होता है । ऐसे बहुत से लोग है जिनको उबहरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुकूल रोजगार के योग्य कौशल प्राप्त करना होता है । शिक्षा हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। समाज में सभी को शिक्षा मिले यही सब का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली के विस्तार के लिए नियमित वेतन भोगी शिक्षकों के स्थान पर अदशिक्षकों को रखा जाने लगा, जिस काल में यह परिवर्तन हुआ वह 2000 के दशक का था, यही वह समय था जब शिक्षा को लोकव्यापी बनाने का अंतराष्ट्रीय अभियान प्रारंभ हुआ। शिक्षा की आधारभूत संरचना के विकास और विस्तार के लिए बहुत सी संस्था आगे आने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की आर्थिक प्रणाली के साथ समंजस हो सके इसका विस्तारित विवरण न केवल जटिल था बल्कि कठिन भी था। नीति निर्धारकों ने नियमित वेतन भोगी शिक्षक के स्थान पर अदशिक्षकों को रखा जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रभाव कम होता गया इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के लिए शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जाये और उन्हें अपने परिश्रमिक का सही वेतन मिल सके। शिक्षा में बदलाव का एक और आधुनिक मसीहा है– सूचना प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में अप्रचलित हो रहे, ज्ञान के साथ–साथ समय और स्थान की कठिनाइयों के कारण दूरस्थ प्रणाली से विभिन्न संस्थाओं के भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए भारी मांग आई है।शिक्षा वास्तविक अर्थो में सत्य की खोज है। यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। ऐसी यात्रा मानवतावाद के विकास के लिए नये रास्ते खोलती है जहां ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, संकीर्णता और वैमनस्य का कोई स्थान न हो। यह मनुष्य को संपूर्ण, श्रेष्ठ, नेक इंसान और विश्व के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनाती है। सही मायनों में विश्व बंधुत्व ऐसी शिक्षा के लिए ढाल बन जाता है। यथार्थपरक शिक्षा मनुष्य की गरिमा और आत्मसम्मान बढाती है। यदि शिक्षा की यथार्थता को प्रत्येक समझ ले और मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अपना ले तो रहने के लिए विश्व और भी बेहतर स्थान बन जाएगा। केंद्र अथवा राज्य या दोनों का शिक्षा मिशन, उन प्रबुद्ध नागरिकों के निर्माण की बुनियाद है जो एक समृद्ध, खुशहाल और मजबूत राष्द्र की रचना करेंगे।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्चशिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान

विमलेश कुमार
असि0 प्रोफेसर, लालाराम महाविद्यालय,
चम्पानेर, इटावा

कु. उदयवीर सिंह पंवार
असि0 प्रोफेसर,
कारगिल शहीद महाविद्यालय,
जसवंतनगर, इटावा

प्रदीप कुमार
असि0 प्रोफेसर,
कर्मक्षेत्र महाविद्यालय,
इटावा

सुनील कुमार पाल
असि0 प्रोफेसर,
लालाराम महाविद्यालय,
चम्पानेर, इटावा

मुकेश सिंह
असि0 प्रोफेसर,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर बौद्ध महाविद्यालय,
न0 खादर, इटावा

प्रस्तावना

शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश या समाज के विकास की धुरी होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज में ज्ञान, नैतिकता, चरित्र का प्रवाह भी उसी तरह का परिलक्षित होगा। प्राथमिक शिक्षा जहां बुनियादी ज्ञान प्रदान करती है, वहीं उच्च शिक्षा देश व समाज की प्रगति के नये–नये मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। आज का विश्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। इस परिवर्तन का आशय यह है कि अब रोजगार के अवसर व उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था में ज्ञान क्षेत्र से आ रही है।

शिक्षा अब एक ऐसा शब्द हो गया है जो सीखने व सिखाने की औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवस्था का पर्याय हो गया है पिछली पूरी सदी में दुनियां भर में शिक्षा के दर्शन और उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण विमर्श और प्रयोग हुये हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षा का दर्शन आज भी बहुत आदर्शवादी है और इसका क्रियान्वयन अभी भी अपनी व्यावहारिक उलझनों से जूझ रहा है। शिक्षा के दार्शनिक पक्ष का अवलोकन करने मात्र से पता चलता है कि यह मनुष्य जाति की सबसे महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी परियोजना है।

20वीं सदी के सबसे सम्मानित व चर्चित नेता महात्मा गांधी शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाओं के प्रतिपादक थे। वे शिक्षा को व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ–साथ देश व समाज की प्रगति की आवश्यकता के

रूप में चिन्हित करते थे। सामाजिक माध्यम से व्यक्ति विकास की बात करते थे। गांधी जी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मातृ भाषा शिक्षा (स्थानीय भाषा), स्वावलम्बन की शिक्षा, अहिंसा की शिक्षा, नागरिक जीवन के आदर्शों की शिक्षा, सहकारिता की शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षा में प्रकृतिवाद जैसे अनेक विषयों पर बल देते हुए शिक्षा की सर्वांगीणता के अग्राही रहे है।

भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनजंख्या ने शिक्षण संस्थानों के विस्तार की आवश्यकता को जन्म दिया जिस पर ध्यान देना, देश व समाज की मजबूरी बन गयी है। इसी से प्रेरित हो कर सन् 2007 में **सैम पित्रोदा** की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत के सभी नौजवानों को पढ़ाई कराने के लिए कम से कम 1500 विश्वविद्यालयों तथा 35000 महाविद्यालयों की आवश्यकता है, जबकि हकीकत यह है कि निजी व सरकारी प्रयास मिलकर इस आवश्यकता को लगभग 50 प्रतिशत ही पूरा कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लाखों नौजवानों को शिक्षा से वंचित होना लाज़मी है, जबकि इससे पूर्व सन् 1996 में शासन द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाने लगी थी।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु तैयार किया गया है –

1. महाविद्यालयी शिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना की अवधारणा का अध्ययन करन।
2. उच्चशिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना की भूमिका व योगदान का अध्ययन करना।
3. उच्चशिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना के गुण एवं दोषों का अध्ययन करना।
4. उच्चशिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना को सफल बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

उच्चशिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना की उत्तर प्रदेश में स्थिति

उत्तर प्रदेश में सन् 1995 तक अनुदानित व राजकीय महाविद्यालय स्थापित थे। अधिकांश तहसीलों, नगरपालिकाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय स्थापित न होने के कारण तथा संसाधनों के अभाव में लाखों छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे और छात्र–छात्राओं की बृद्धि के अनुपात में निजी व राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन न होने के कारण प्रतिवर्ष प्रवेश की समस्या जटिल होती जा रही थी। इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन में बृद्धि के साथ–साथ निजी क्षेत्र में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रदान करना प्रारम्भ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वंचित छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त होने लगे। साथ ही प्रवेश की समस्या कुछ हद तक कम हो गयी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सन् 1996 से अनुदानित महाविद्यालयों के रूप में सम्बद्धता प्रदान किया जाना पूर्णतया बंद कर दिया गया तथा स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करना आरम्भ कर दिया गया। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानको का निर्धारण करने के सम्बंध में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा की गयी संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरांत शासन के पत्र संख्या : 1960/सत्तर–2–97–2 (85)/97 उच्च शिक्षा अनुभाग 2 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के द्वारा किया गया तथा स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में संकाय विस्तार सम्बंधी मानकों का निर्धारण दिनांक 11.11.1997 से सितम्बर 2002 तक विभिन्न शासनादेशों के द्वारा किया गया। उक्त सभी शासनादेशों में दिये गये सम्बद्धता सम्बंधी मानको का शासनादेश 27 सितम्बर 2002 में समायोजित करके विस्तृत विवरणों सहित मानकों का निर्धारण किया गया है।

उच्च शिक्षा में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया व वेतन सम्बंधी प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनेक शासनादेशों के बावजूद अनेकों कमियां मौजूद है जो समाज व देश के समक्ष एक जटिल समस्या बन चुकी है। इनमें से कुछ समस्याएं निम्न हैं :

1. अधिकांश स्ववित्तपोषी संस्थाओं में यू0जी0सी0 के मानकानुसार शिक्षक कार्यरत नहीं, अगर है तो केवल दस्तावेजों पर ही दिखाई देते है, ऐसे शिक्षक धन के लालच में एक से अधिक संस्थाओं में अनुमोदित है। इस तथ्य को महामहिम कुलाधिपति ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है तथा उत्तर प्रदेश शासन व प्रदेश के कुलपतियों को निर्देश भी जारी कर चुके हैं।
2. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को अकुशल श्रमिक से भी कम पारिश्रमिक वेतन के रूप में दिया जाता है। कुछ अनुमोदित शिक्षकों को यह वेतन 5 से 6 माह ही दिया जाता है।
3. कुछ महाविद्यालों में तो वेतन के नाम पर 5 से 8 हजार रूपये नकद दे दिये जाते हैं, तथा विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा वेतन विवरण मांगे जाने पर अनुमोदित शिक्षकों का वेतन विवरण फर्जी तरीके से तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें विश्वविद्यालय एवं शासन को गुमराह करने में प्रबंधन वर्ग कामयाब हो जाता है तथा कहीं–कहीं यह भी आसानी से देखा जा सकता है कि प्रबंधन वर्ग द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के बैंक खाते खुलवाकर पासबुक, चैकबुक एवं एटीएम अपने पास सुरक्षित रखवा लेते है तथा उन खातों का संचालन स्वयं करते हैं।
4. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षण कार्य से ज्यादा गैर शिक्षण कार्यों को प्रबंधन के दबाब में करने को मजबूर रहते हैं जिससे उनमें हीन भावना तथा छात्रों में अनुशासन को बढ़ावा मिलता है।
5. अधिकांश स्ववित्तपोषित संस्थानों में मानकों के अनुरूप अवसंरचना सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है।
6. अधिकांश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य कराने हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं होते है।
7. नब्बे प्रतिशत स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अनुमोदित प्रचार्य कार्यरत नहीं है, उनके स्थान पर प्रबंधनतंत्र के व्यक्ति कार्य करते हैं, जो अपने मनमाने तरीके वित्तीय स्थितियों में गम्भीर गड़बड़ियां करते है।
8. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के दौरान अधिकांशतः प्राचार्यों को बीमार घोषित करके अनुमोदित अथवा प्रबधंनतंत्र अपने अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्ति को वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करवा लेते हैं।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता एवं शिक्षा के गिरते स्तर को उन्नत बनाने हेतु निम्न उपाय कारगर साबित हो सकते हैं :

1. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समस्त विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
2. उच्च शिक्षा में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा केन्द्रीकृत की जानी चाहिए ताकि नकल की संभावनाओं को कम किया जा सके।
3. महाविद्यालय को शिक्षक छात्र अनुपात जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4. विश्वविद्यालय को चाहिए सत्र् के मध्यावधि में महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर महाविद्यालयों के लेखा एवं शिक्षण कार्य का अवलोकन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
5. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन नीति का पालन कते हुए शिक्षकों का वेतन शासन द्वारा दिया जाना चाहिए।
6. विश्वविद्याय स्तर प्रवेश प्रक्रिया पर सम्पन्न कराना चाहिए ताकि महाविद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात को सही किया जा सकें।
7. विश्वविद्यालय द्वारा दिये जा रहे अनुमोदन के समय शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराकर आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक अथवा महाविद्यालयों के प्रबंधन के लोग एक से अधिक स्थान पर दस्तावेजों का दुरूपयोग न कर सके।
8. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडी की टीम में वरिष्ठता क्रम के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।
9. इन महाविद्यालयों में लिये जाने वाला शुल्क विश्वविद्यालय अपने खाते में चालान अथवा आरटीजीएस के द्वारा जमाकर करवा कर 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के खोते में वेतन स्वरूप सीधे भेजा जाना चाहिए। जिससे विश्वविद्यालय की आय में बृद्धि सम्भाव्य होगी।
10. विश्वविद्यालयी परीक्षा को सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान करने वाले शिक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक शिक्षकों के खाते में सीधे भेजा जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सके।
11. उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की अनुमति शिक्षाविदों को ही दी जानी चाहिए, राजनेताओं अथवा व्यासायियों को नहीं ताकि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में हो रहे व्यावसायीकरण एवं राजनीतिकरण को रोका जा सके।

निष्कर्ष

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षा के स्तर का उन्नत बनाना लक्ष्य होना चाहिए धन कमाना नहीं। तभी देश को शिक्षित व कुशल नागरिक प्राप्त होंगे जिससे देश का विकास होगा। वर्तमान में चल रही शिक्षा व्यवस्था देश के विकास में तो नहीं, विनाश में अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए समय से पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरस्त करने की आवश्यकता है नही ंतो देश व समाज का गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. निदेशक, उच्च शिक्षा अनुभाग से प्रकाशित शासनादेश।
2. कुरूक्षेत्र, वर्ष 56, अंक 11, सितम्बर 2010।
3. कुरूक्षेत्र, वर्ष 59, अंक 11, सितम्बर 2013।
4. योजना, वर्ष 43, अंक 4, जुलाई 1999।

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा, समस्या चुनौतियाँ एवं सुधार

सरवर जहॉ
प्रवक्ता एवं विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग
बृहस्पति पी0जी0 कॉलेज
के0 ब्लॉक किदवई नगर कानपुर

उच्च शिक्षा का अर्थ है समान्य रुप से दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय में विशेष शिक्षा। उच्च शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। जो अधिकांशतः विश्वविद्यालय में भी दी जाती है तथा यही से देश एवं राष्ट्र एवं निर्माण की नीव पड़ती है। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है लेकिन क्या यह हमारें देश की उच्च शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ती करने में सफल हुये है। यह एक बड़ा प्रश्न है देश की उच्च शिक्षा को शिक्षा की मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा।

वर्तमान में केन्द्र सरकार नई शैक्षणिक नीति बनाने की कोशिश कर रही है। यह अच्छी बात है इससे एजुकेशन एक कदम आगे बढ़ेगी लेकिन यह करते समय यह ध्यान रखना जरुरी है कि शिक्षा को लेकर जो कदम उठाये गये थे उनको बिल्डअप करने की जरुरत है। असकी वजह यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2006 से लेकर 2011 तक उच्च शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया गया था। उससे उस शिक्षा की समस्याएं क्या–क्या हैं यह पता लगाकर उसका अध्ययन किया गया और एसके आधार पर नीति बनायी गयी डिजिटल होने और दुनिका की आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना सजो रहें। भारत में उच्च तकनीकि और प्रबंधन शिक्षा का ढॉचा चरमराता दिख रहा है। देश व समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा नीतियों में जल्द बुनियादी बदलाव कर देश के शैक्षणिक विकास का इतिहास गौरवशाली बनाया जाये।

उच्च शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा का सबसे महत्वर्पण स्तर होता है जो विश्वविद्यालयों से बड़े संस्थानों में दी जाती है। उच्च शिक्षा जो राष्ट्र की आधार शिला होती है उससे गुणवत्ता और स्वायत्ता का सवाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी भारी संख्या में विद्यार्थी बेरोजगार बने रहते है। कुछ को छोड़ दे तो ज्यादातर विषयों का जीवन की वास्तविकताओं से संबंध कम ही होता है। इस तरह यह शिक्षा ज्यादातर त्रासदी ही रचती है। इसमें दो स्तरों पर बदलाव की जरुरत है एक एकेडमिक्स् में नवाचार, दूसरा विलयों को जीवन से जोड़कर अजीविका पक्ष की मजबूती।

विश्व के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत न केवल विकसित राष्ट्रो से काफी पीछे है, बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी दृष्टि में भारत से आगे है। एक तरफ कक्षा में क्षमता से अधिक संख्या प्रयोशालाओं की कमी लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में 40 प्रतिशत शिक्षकों की कमी और ऊपर से रोज–रोज बढ़तें राजनैतिक दबाव आदि। उच्च शिक्षा में तीन प्रमुख कार्य करने होते है। शिक्षण, शोध तथा अकादमिक प्रशासन किसी भी शिक्षक का समान रुप से तीनों पर अधिकार होना आसान कार्य नही है। किसी की शिक्षण में अधिक रुचि होगी तो किसी की शोध में तथा किसी में अकादमिक प्रशासनिक दायित्वों को अच्छी तरह निभाने की क्षमता होगी। ए0पी0आई0 (अकादमिक कार्य निष्पादन सूचक) व्यवस्था के माध्यम से सभी को एक जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम मजबूत करने के बजाये जिसमें यह

कमजोर है उसमें अधिक समय दे रहा है क्योंकि प्रमोशन में उसे इन तीनों में अपनी दक्षता प्रदर्शित करनी होती है। ए0पी0आई0 व्यवस्था लागू होने के बाद रिसर्च जनरल, शोध संगोष्ठियॉ, शोध सेमीनार तथा पुस्तकों की बाढ़ सी आयी है। उनकी संख्या के आधार पर यह अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा में हम कितनी गुणवत्ता रख पा रहें होंगे। शोध में गुणवत्ता बहाली के लिये हमें शोध अनिवार्य बल्कि एच्छिक करना होगा। शोध में सिर्फ वों ही आगे बढ़े जिनकी वास्तव में शोध में रुचि हो।

उच्च शिक्षा में सुधार

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक संस्कृति का विकास करना चाहिए जिससे शिक्षकों व विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुक्ता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाये रख सकती है। राष्ट्र स्तर पर वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली यू0जी0सी0 नेट परीक्षा को एम0फिल, पी0एच0डी0 में प्रवेश, छात्रवृत्ति एवं छात्रों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के लिये भी आधार बनाया जा सकता है। शोध कार्यों के लिये संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है। हमें कड़ियों की भूमिका का निस्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आ पायेगा।

शिक्षक व विद्यार्थी की स्वयत्ता को बुहत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बड़ा कार्य सम्भव है। इस योजना में उन सरकारी कॉलेजों को अतिरिक्त धन एवं सुविधायें दी जाती है। जहॉ प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाये।

भारत युवाओं का देश है मेक इन इण्डिया जैसी अहम योजनाओं को सफल बनाना है तो इसके लिये युवाओं को सही राह दिखानी होगी उसके लिये जरुरी है कि हमारें छात्रों को बहतर उच्च शिक्षा दी जाये। स्कूल शिक्षा में पहले सुधार जरुरी तभी उच्च शिक्षा में बढ़े स्तर पर गुणवत्ता सुधार सम्भव होगा। अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एन0सी0टी0ई0 एक्ट में परिवर्तन किये गये है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी संशोधित किया गया है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों शुल्क में पूरी छूट मिलनी चाहिए इस संसाधनों में प्रवेश का आधार केवल मैरिट ही होना चाहिए।

उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के संसाधनों की मदद करने में कोष प्रदान करने, विद्यार्थियों को कर्ज दिलाने में वित्तीय गारन्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरुपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जायें।

भारत देश को अगर 2020 सुपर पावर बनाना है तो उसके लिये पढ़े–लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरुरत है। शैक्षिक संस्थान वस्तुता नही पैदा करती वे मनुष्य रचते है और ज्ञान के द्वारा उसका परिमार्जन करते है। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की कल्पना कर रहे है? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति के साथ उन क्षेत्रो को रेखांकित करे जिनमे परमाणिक रूप से योगदान सम्भव है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.google.com
2. www.timehighereducation.com
3. Higher Education for 21st Century Singh J.D.
4. bhartiyashiksha.com
5. crisis In Higher Education Rani Mehta

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा : समस्याएं, चुनौतियाँ एवं सुधार

शिल्पी वर्मा
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
ब्रहस्पति डिग्री पी0जी0 कॉलेज
कानपुर

उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय में विशेष शिक्षा। उच्च शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है जो अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में दी जाती है तथा यहीं से देश एवं राष्ट्र निर्माण की नीव पड़ती है स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा, छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुयी है। यह एक बड़ा प्रश्न है। देश की उच्च शिक्षा को शिक्षा की मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा।

वर्तमान में केन्द्र सरकार नई शैक्षणिक नीति बनाने की कोशिश कर रही है यह अच्छी बात है इससे एजुकेशन एक कदम आगे बढ़ेगी, लेकिपन यह करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इससे पहले शिक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए थे, उनको बिल्डअप करने की जरूरत है इसकी वजह यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2006 से लेकर 2011 तक उच्च शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया गया था। उससे उच्च शिक्षा की समस्याएं क्या–क्या हैं, यह पता लगाकर उसका अध्ययन किया गया और उसके आधार पर नीति बनाई गई। डिजिटल होने और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना संजो रहे भारत में उच्च, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा है। देश व समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा–नीतियो में जल्द बुनियादी बदलाव कर देश के शैक्षणिक विकास का इतिहास गौरवशाली बनाया जाए।

उच्च शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। जो विश्विद्यालयों सा बड़े संस्थानों में दी जाती है। उच्च शिक्षा जो राष्ट्र की आधारशिला होती हे उसमें गुणवत्ता और स्वायत्तता का सवाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दोनों इसके महत्वर्पूा पहलू हैं इसके बिना शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी यह कहना शायद बहुत बड़ी भूल होगी और शिक्षा में विशेषकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता स्वायत्तता के अभाव में असम्भव भले न हो किन्तु कठिन जरूर है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता इसलिए जरूरी है कि इसके अंतर्गत आने वाले अनुशासन सर्वाधिक कुशलता की मांग करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री या विभिन्न विषयों के विद्वान, शोधार्थी इनकी गुणवत्ता है इन्हें सफल बनाती है।

वर्तमान समय में भारत में गुणवत्ता व स्वायत्तता उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। गुणवत्ता से तात्पर्य उच्च शिक्षा का उन समस्त मानको पर खरा उतररना है जिनको ध्यान में रखकर यह प्रदान की जा रही है। यदि शिक्षा वर्तमान जीवन की चुनौतियों को कुशलतापूर्वक हल कर देती है। छात्र को अतयधिक दक्ष बनाती है व इसे उस योग्य बनाती है कि वह नवीन ज्ञान का सृजन कर सकें।

भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियाँ

उच्च स्तर की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-12* January- 2019
Innovation The Research Concept

बनी रही है। योजना बनाना व पालन करवाना यू0जी0सी0 और सरकार का काम है परन्तु सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने में निरन्तर विफल रही है। उच्च शिक्षा में ऐसी गुंजइश होनी चाहिए कि व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद सक्रिय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। वह समाज का टापू न लगे। यदि टापू भी हो तो सर्जनशीलता का मन लिए हो जिसमें आम आदमी भी बसा हो। मानविकी के विषयों में संवेदन, प्रेक्षण, विवेचन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि थोड़ा बारीकी से देखें तो पायेंगे कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के उपरान्त भी भारी संख्या में विद्यार्थी बेरोजगार बने रहते हैं। कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर विषयों का जीवन की वास्तविक्ताओं से संबंध कम ही होता है। इस तरह यह शिक्षा ज्यादातर त्रासदी ही रचती है। इसमें दो स्तरों पर बदलाव की जरूरत है एक एकेडमिक्स में नवाचार, दूसरा विलयों को जीवन से जोड़कर आजीविका पक्ष की मजबती।

विश्व के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत न केवल विकसित राष्ट्रों से काफी पीछे है, बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी इस दृष्टि से भारत से आगे हैं। एक तरफ कक्षा में क्षमता से अधिक संख्या, प्रयोगशालाओं की कमी। लगभग सभी प्रममुख संस्थानों में चालीस प्रतिशत शिक्षकों की कमी और ऊपर से रोज–रोज बढ़ते राजनीतिक दबाव आदि। उच्च शिक्षा में तीन प्रमुख कार्य करने होते हैं– शिक्षण, शोध तथा अकादमिक प्रशासन। किसी भी शिक्षक का समान रूप से तीनों पर अधिकार होना आसान कार्य नहीं है। किसी की शिक्षण में अधिक रूचि होगी तो किसी की शोध में तथा किसी में अकादमिक प्रशासनिक दायित्यों को अच्छी तरह निभाने की क्षमता होगी। ए0पी0आई0 (अकादमिक कार्य निष्पादन सूचक) व्यवस्था के माध्यम से सभी को एक जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रीाााव मजबूत करने के बजाय जिसमें वह कमजोर है उसमें अधिक समय दे रहा है क्योंकि प्रमोशन में उसे इन तीनों में अपनी दक्षता प्रदर्शित करनी होती है। ए0पी0आई0 व्यवस्था लागू होने के बाद रिसर्च जर्नल, शोध संगोष्ठियां शोध सेमीनार तथा पुस्तकों की बाढ़ सी आई है। इनकी संख्या के आधार पर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा में हम कितनी गुणवत्ता रख पा रहे होंगे। शोध में गुणवत्ता बहाली के लिए हमें शोध अनिवार्य बलिक ऐच्छिक करना होगा। शोध में सिर्फ हो ही आगे बढ़ें, जिनकी वास्तव में शेध में रूचि हो।

उच्च शिक्षा में सुधार

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक संस्कृति का विाकस करना चाहिए जिससे शिक्षकों व विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली यू0जी0सी0 नेट की परीक्षा को एम0फिल, पी0एच0डी0 में प्रवेश, स्कालरशिप एवं छात्रों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार बनाया जा सकता है। शोध कार्यों के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है। हमें कड़ियों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापाक बदलाव आ पाएगा।

शिक्षक व विद्यार्थी की स्वायत्तता को बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बड़ा कार्य संभव है। इस योजना में उन सरकारी कालेजों को अतिरिक्त धन एवं सुविधाएं दी जाती हैं। जहां प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाए।

भारत युवाओं का देश है। मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया जैसी अहम योजनाओं को सफल बनाना है तो इसके लिए युवाओं को सही राह दिखानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे छात्रों को

बेहतर उच्च शिक्षा दी जाए। स्कूली शिक्षा में पहले सुधार जरूरी तभी उच्च शिक्षा में बड़े स्तर पर गुणवत्ता सुधार संभव होगा। अध्यापक प्रशिक्षण के क्षत्र में एन0सी0टी0ई0 एक्ट में परिवर्तन किए गए हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी संशोधित किया गया है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। कमज़ोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में शुल्क में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन संस्थानों में प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।

उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के संस्थानों की मद्द करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियों के कर्ज दिलााने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठयक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।

भारत देश को अगर 2020 तक सुपर पाव बनाना है तो उसके लिए पढ़े–लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरूरत है। शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति के साथ उन क्षेत्रों को रेखांकित करें जिनमें प्रमाणिक रूप से योगदान सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *www.google.com*
2. *www.timehighereducation.com*
3. *Higher Education for 21st Century: Singh J.D.*
4. *Bharatiyashiksha.com*
5. *Crisis In Higher Education : Rani Mehta*